RNI NO. RAJHIN/2013/57419

राजस्थान का सर्वाधिक ई-पेपर दैनिक

द पुलिस पोस्ट

अंदोलन नहीं अखबार

जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा से प्रसारित

जयपुर
बुधवार
21-अगस्त,2024

वर्ष: 10: अंक: 125

दूरभाष: 01482: 433184: पृष्ठ: 08: मूल्य: 1.50 रुपए

विभिन्न संगठनों के आह्वान पर भारत बंद आज

किरोड़ी लाल मीणा बोले : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य, वंचित वर्ग को मिले आरक्षण का लाभ

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(निसं.)। अनुसूचित जाति जनजाति की ओर से बुधवार को बंद के आह्वान के बीच बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले विधायक डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने मंगलवार को कहा कि अब वंचितों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मीणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि आज मेरा परिवार क्रिमिलेयर में है, मेरा भाई प्रशासनिक अधिकारी रह चुका, जबकि मेरा पड़ोसी आज भी पत्थर ही तोड़ रहा है। उसका बेटा भी यही काम कर रहा है इसलिए वंचित वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए। इधर 21 अगस्त को अनूसूचित जाति-अनूसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में 12वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अवकाश

घोषित किया गया है। इस दौरान सभी कोचिंग संस्थान व स्कूल 21 अगस्त को बंद रहेंगे। जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करते हुए कहा कि बंद के दौरान जयपुर में रैली, प्रदर्शन व जाम की स्थिति रह सकती है। ऐसे में स्कूली बच्चे वाहनों में फंसे रह सकते हैं। इसलिए कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। स्कूल के अलावा जिले में सभी कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।

केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा अवकाश

जयपुर के अलावा दौसा, बाड़मेर और डीग समेत कई जिलों में भी 12वीं तक के सरकारी व प्राइवेट स्कूल में 21 अगस्त को छुट्टी रहेगी। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों व सभी कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी में भी अवकाश घोषित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा, बाकि अन्य स्टाफ तय समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

कई राजनीतिक दलों ने बंद का किया समर्थन

राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन सड़कों पर उतरने से दूरी बनाई है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारा भारत बंद को समर्थन है, लेकिन सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन, शहर बंद जैसा कोई काम नहीं करना है। इसके अलावा बसपा ने भी बंद का समर्थन किया है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगी।

न्यूज इनबॉक्स

बांग्लादेश से छिनी महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी, अब यूएई को

द पुलिस पोस्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने महिला टी 20 विश्व कप की मेजबानी मंगलवार को बांग्लादेश से छीन ली है। तीन से 20 अक्टूबर तक होने वाला यह वैश्विक टूर्नामेंट अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में खेला जाएगा। क्रिकेट की वैश्विक संस्था ने यह फैसला बांग्लादेश में भारी उथल-पुथल और हिंसा को देखते हुए लिया है। मालूम हो कि पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति बनी हुई है जिस कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद और देश छोड़ना पड़ा था। महिला टी20 विश्व कप के मुकाबले अब दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी जियोफ एलार्डिस ने कहा कि बांग्लादेश के लिए महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी नहीं करना निराशाजनक है क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने एक यादगार आयोजन की तैयारी की थी।

राजस्थान में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की जान को खतरा। प्रदेश में 3000 से ज्यादा सर्जरी टली

जयपुर (कासं.) कोलकाता रेप और हत्या मामले में देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। इससे राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर भी अछूते नहीं है। उन्होंने भी न्याय और सुरक्षा को लेकर पिछले 8 दिनों से मोर्चा खोल रखा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों का मूड अभी ऐसा नहीं लग रहा है। राजस्थान प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। प्रदेश भर में ओपीडी सेवाओं के साथ साथ इमरजेंसी सेवा और सर्जरी भी प्रभावित हुई है। हालात ऐसे हैं कि हड़ताल से परेशान मरीजों ने अब सरकारी अस्पतालों से दूरी बना ली ह। प्रदेश के अस्पतालों में अब तक हजारों सर्जरी टाली जा चुकी है। इसके बाद अस्पतालों में मरीजों की कतार दिखाई नहीं दे रही। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में ओपीडी सेवाओं में मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों ने 12 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया था। इसके बाद 13 अगस्त को मरीजों को घंटो लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा था. 12 अगस्त से पहले 1 सप्ताह के दौरान एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में 54 हजार 559 मरीज इलाज के लिए आए थे.।वहीं हड़ताल के बाद अगले एक सप्ताह के दौरान सिर्फ 39 हजार 333 मरीज एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सर्जरी में भी भारी गिरावट देखी गई। एसएमएस अस्पताल में औसतन एक दिन में 400 से 450 सर्जरी होती है।

अजमेर सेक्स स्कैंडल में 32 साल बाद 6 आरोपियों को उम्रकैद

द पुलिस पोस्ट

अजमेर(निसं.)। राजस्थान के 1992 के बहुचर्चित अजमेर सेक्स और ब्लैकमेल कांड में मंगलवार को बड़ा फैसला आया है। 6 दोषियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी 6 दोषियों पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले अजमेर के पॉक्सो कोर्ट ने सुबह ही 6 आरोपियों को दोषी ठहराया था। ये मामला मेयो कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं से जुड़ा है, जिनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई थी। 32 साल बाद इस मामले में फैसले के समय सभी दोषी कोर्ट में मौजूद रहे।

32 साल पहले कॉलेज की 100 से ज्यादा छात्राओं के साथ रेप

यह मामला 32 साल पुराना है, जब अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज की 100 से ज़्यादा छात्राओं को आरोपियों ने फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया था। आरोपियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीन हुसैन शामिल हैं। पोक्सो कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया है। दोषी पाए जाने के बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और दोपहर 2 बजे फैसले के समय फिर से कोर्ट में पेश किया।

30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

बेशर्मी की हद पार, कोर्ट में चेहरे पर मुस्कान

कॉलेज की सौ से ज्यादा लड़कियों के साथ दरिंदगी करने वाले ये दोषी जब कोर्ट पहुंचे तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। दोषी करार दिए जाने से पहले वो एक दूसरे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए। हालांकि उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी गर्दन झुकी थी। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सभी दोषियों को अजमेर जेल भेज दिया गया।

18 आरोपी थे, 9 को पहले ही मिली सजा

इस मामले में कुल 18 लोग आरोपी थे। इनमें से 9 को पहले ही सज़ा हो चुकी है, जबकि एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी। एक अन्य आरोपी पर एक बिजनेसमैन के बेटे से कुकर्म के आरोप में अलग से केस चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। इस मामले में 6 आरोपियों की ट्रायल इसी साल जुलाई में पूरी हुई थी और 8 अगस्त को फैसला आना था। लेकिन अब जाकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसले के बाद सभी की निगाहें अब सज़ा की अवधि पर टिकी थी।

कांग्रेस पार्टी नहीं उतारेगी उम्मीदवार, बिट्टू का सांसद बनना तय

राजस्थान में रवनीत सिंह बिट्टू भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार

द पुलिस पोस्ट

नई दिल्ली(एजेंसी)। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राजस्थान कैबिनेट मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। रवनीत सिंह बिट्टू बुधवार को नामांकन दाखिल करेंगे। मालूम हो कि राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होना है। यह सीट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई थी।

रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा सांसद बनना तय

विधानसभा चुनाव 2023 में मिली जीत के बाद भाजपा के पास पर्याप्त संख्याबल है। कांग्रेस ने राज्यसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने की घोषणा की है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राजस्थान का राज्यसभा सांसद बनना लगभग तय है। भाजपा ने 9 सीटों पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार को उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें राजस्थान से

रवनीत सिंह बिट्टू का नाम शामिल है। जबकि असम से मिशन रंज दास, रामेश्वर तेली का नाम शामिल है। बिहार से भाजपा ने मनन कुमार मिश्र को उम्मीदवार है। हरियाणा के किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। काबिले गौर है कि राजस्थान से भाजपा ने जिस रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, वो लोकसभा चुनाव 2024 में लुधियाना सीट से लड़े थे। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद भी रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया था।

देश के राजनीतिक हालात चिंताजनक: डोटासरा

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में आठ महीने में सरकार सही से काम नहीं कर पाई। डोटासरा ने कहा कि यह पर्ची सरकार है। यहां पर्चियों से चलती है। अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आज केंद्र में बैठे हुए लोग केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए काम कर रहे हैं। देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देश में धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देश के हालात गृह युद्ध जैसे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरों में व्यस्त हैं। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। 400 पार के चक्कर में 250 भी नहीं ला पाए। संविधान खतरे में है। आरक्षण की व्यवस्था खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है। ये 'वन नेशन, वन इलेक्शन', 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की बात कर रहे हैं। आपने नमूना देख लिया। अभी चार राज्यों में से दो राज्यों के चुनाव घोषित किए हैं। राजस्थान

की 6 सीटों के उपचुनाव भी घोषित नहीं किए। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि बरसात में हालात ठीक नहीं हैं। तो जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' और 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' करेंगे तो क्या बरसात रुक जाएगी? मई में लोकसभा चुनाव इतने लंबे यानी कई फेज में करवाए तो एक साथ चुनाव कैसे संभव होंगे? ये केवल सत्ता के लिए इस तरह के जुमले फेंकते हैं। उपचुनाव में गठबंधन के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि गठबंधन लोकसभा चुनाव में था। गठबंधन कभी भी किन परिस्थितियों में कहां, किस स्तर पर करना है, यह पार्टी हाईकमान का सब्जेक्ट है।

सिक्किम के बालूतार में हुआ भयावह भूस्खलन, तीस्ता डैम पावर स्टेशन तबाह

बालुतार(एजेंसी)। सिक्किम के बालूतार में मंगलवार की सुबह भीषण भूस्खलन आया। इसके कारण वहां स्थित नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के तीस्ता स्टेज 5 बांध का पावर स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पहाड़ के एक बड़े हिस्से को पावर प्लांट पर गिरता हुआ देखा जा सकता है। राहत ही बात यह रही कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। दरअसल, बिजलीघर को कुछ दिन पहले ही खाली करा लिया गया था। हालांकि, बिजलीघर पर काम कर रहे

कर्मचारियों ने भूस्खलन को अपने फोन पर रिकॉर्ड

कर लिया है। बता दें कि सिक्किम में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। अक्टूबर 2023 में तीस्ता नदी बेसिन में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद स्टेज 5 बांध निष्क्रिय हो गया था। बाढ़ के कारण नष्ट हुए बांध का पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

राजस्थान में नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर उपचुनाव की घोषणा

द पुलिस पोस्ट

जयपुर(कासं.)। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के नगरीय निकायों के विभिन्न रिक्त पदों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। 11 जिलों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव संचिता बिश्नोई ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सचिव संचिता बिश्नोई ने बताया कि प्रदेश के 11

जिलों बारां, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जालोर, गंगापुर सिटी, कोटा, श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ के कुल 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। सदस्य के लिए मतदान 5 सितंबर, अध्यक्ष के लिए मतदान 17 सितंबर और उपाध्यक्ष के लिए मतदान 18 सितंबर को कराए जाएंगे। संचिता बिश्नोई ने बताया कि सदस्य पद के उपचुनाव के लिए मंगलवार को लोक सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त प्रात: 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 27 अगस्त को सुबह 10:30 बजे की जाएगी। वहीं 29 अगस्त अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिह्नों का आवंटन 30 अगस्त को किया जाएगा। 5 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं 6 सितंबर को सुबह 9 से मतगणना की जाएगी।

अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और मतदान की तारीख

इसी प्रकार अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना 9 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक रहेगी। 11 सितबर को सुबह 10:30 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। 12 सितंबर अपराह्न 3:00 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद 12 सितंबर को ही चुनाव चिह्नों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 17 सितंबर को सुबह 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 तक होगा और मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।

उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन और मतदान की तारीख तय

उपाध्यक्षीय पदों के लिए निर्वाचन की तिथि 18 सितंबर निर्धारित की गई है। इस दिन सुबह 10 बजे बैठक शुरू की जाएगी। सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्रों का प्रस्तुतीकरण, सुबह 11:30 से नामांकन पत्रों की संवीक्षा और अपराह्न 2 तक नाम वापसी की जा सकेगी। आवश्यक होने पर अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी।

ब्रह्माकुमारी ने रक्षा सूत्र बांध दिया प्रेम व सौहार्द का संदेश

देश का सबसे बडा संगठन आई एफ डब्ल्यू जे के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष शिवगंज ब्लॉक अध्यक्ष ने रक्षाबंधन की बधाई दी

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज। भाई व बहिन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षा बंधन शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बहिनों ने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांध कर रक्षा का वचन लिया। रक्षा बंधन के दिन दोपहर 1 बजकर 31 मिनट तक भद्रा होने की वजह से इस समय के पश्चात बहिनों ने भाईयों के राखी बांधी। रक्षा बंधन के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा की संचालिका पूनम बहन ने पुलिस अधिकारियों सहित प्रबुद्धजनों के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर प्रेम व सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान ब्रह्माकुमारी पूनम बहन मंदबुद्धि आवासीय विद्यालय भी पहुंची तथा वहां रह रहे मंद बुद्धि बच्चों एवं वहां के स्टाफ सदस्यों के भी राखी बांधी। रविवार व सोमवार को भी गांधीनगर स्थित संस्थान

की शाखा पर आयोजित कार्यक्रम में सैकडों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर संस्थान पर आने वाले सभी भाई बहिनों के राखी बांध प्रजापिता शिव बाबा का संदेश दिया। रक्षा बंधन के अवसर पर पूनम बहन ने पुलिस उप अधीक्षक भवानीसिंह इंदा, तहसीलदार श्यामसिंह चारण,पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा, पंचायत समिति के अतिरिक्त विकास अधिकारी राजेन्द्र सिंह राठौड़, न्यायालय के कार्मिकों व अधिवक्ताओं सहित सुमेरपुर थाना में कार्यरत पुलिस अधिकारियों व पुलिस कर्मियों, सहित कई प्रबुद्धजनों के रक्षा सूत्र बांधा। आई एफ डब्ल्यू जे संगठन की तरफ से रक्षाबंधन की बधाई दी रक्षाबंधन पर्व पर भारत का सबसे बडा संगठन आई एफ डब्ल्यू जे के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्रसिह राठौड सिरोही जिला अध्यक्ष अशोक कुमार कुमावत शिवगंज ब्लॉक अध्यक्ष जैसाराम माली ने ब्रह्मकुमारी की बहनो को रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाए दी

नाकाबंदी में पुलिस ने पकड़ा तीन क्विंटल डोडा पोस्त,तस्कर अंधेरे का फायदा उठा हुए फरार

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में चलाया जा रहा है मादक पदार्थो की रोकथाम के अभियान

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता बस तस्कर भाग गए कब हाथ आएगे

शिवगंज। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थो की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शिवगंज पुलिस ने रविवार की रात को बादला गांव के समीप नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा कार से 314 किलो डोडा पोस्त बरामद करने में सफलता हासिल की है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस उप अधीक्षक भवानीसिंह इंदा ने बताया कि पुलिस की ओर से मादक पदाथो की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवार की रात को शिवगंज थाने के पुलिस निरीक्षक बाबूलाल राणा ने मय दल जिसमें सहायक उप निरीक्षक प्रेमसिंह,कॉस्टेबल पप्पाराम, टेकाराम, दिनेश कुमार, प्रकाश कुमार, चालक नारायणसिंह, रामसिंह आरएसी कॉस्टेबल, प्रेमप्रकाश आरएसी कॉस्टेबल शामिल थे ने बादला गांव के समीप नाकाबंदी की।

नाकाबन्दी के दौरान रात्रि डेढ बजे रघुनाथपुरा की तरफ से एक काले रंग की क्रेटा कार को आता देख उसे रूकने का इशारा किया, तो कार चालक पुलिस को देख कार को काम्बेश्वर महादेव मन्दिर जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ कर तेजगति से कार भगाने लगा। जिस पर थानाधिकारी ने पुलिस दल के साथ कार का पीछा किया। कार चालक ने कार को भगाने की पुरी कोशिश की, मगर अपने आप को चारों तरफ से घिरा देख कार चालक अपनी कार को काम्बेश्वर महादेव मन्दिर के प्रवेश द्वार से पहले अपनी कार को रोड़ के साईड मे उतार कर अपने साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति के साथ कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तस्करों का पुलिस ने पीछा भी किया,मगर अन्धेरा व पहाडी इलाका होने की वजह से आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के अनुसार कार की तलाशी लेने पर उसमें कुल 16 प्लास्टिक के कट्टे मिले जिसमें करीब 314 किलो डोडा पोस्त भरा हुआ मिला। जिस पर पुलिस ने डोडा पोस्त व काले रंग की क्रेटा कार को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने मामला एनडीपीसी एक्ट में दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाशी शुरू की है

तस्करो के फरार होने का मलाल है पुलिस प्रशासन को :

तस्करो ने इस रास्ते को आसन समझ लिया है अगर यह तस्कर कुकडीखेडा की तरफ चले गए होते तो हाथ नही आते काम्बेश्वर महादेव मन्दिर के आसपास बडी होटलो व रिसोर्ट मे यह धंधा चल रहा है हजारो रुपए बिधा की जमीन का करोड़ो रूपए होना समझ जाओ तस्करी के लिए इसलिए भाव बढे है मादक पदार्थ की तस्करी व अन्य अवैध कार्य हो रहे है इन होटलो और रिसोर्ट मे अगर पुलिस बराबर निगरानी रखे तो और बडी कामयाबी मिल सकती है क्यो की मेवाड से आने जाने के तीन चार रास्ते है सब पर मुखबिरी मजबूत करनी पड़ेगी तब जाकर पुलिस प्रशासन को बडी कामयाबी हासिल होगी।

लापरवाही ने ली युवक की जानः

लोहे की जाली से बांधा रखा हाईटेंशन लाइन का जॉइंट, बॉल लेने गए युवक का सिर वायर के टच हुआ, मौके पर हुई मौत

द पुलिस पोस्ट

कोटा। क्रिकेट खेलते समय करंट लगने से 16 साल के युवक की मौत हो गई। घटना नांता थाना क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ अपार्टमेंट की है। बताया जा रहा है अपार्टमेंट में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते समय गेंद बिजली की हाइटेंशन लाइन के जॉइंट के पास चली गई। युवक गेंद को लेने हाईटेंशन लाइन जॉइंट के पास चला गया। झुककर गेंद उठाते समय उसका सिर वायर के टच हो गया। युवक मौके पर ही झुलस गया। परिजनों ने बिजली कंपनी केईडीएल व सोसायटी पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। मृतक विशू उर्फ कालू बैरवा (16) मूलरूप से निमोदा हरिसिंह का रहने वाला था। पिछले दो साल अपने परिजनों के साथ पार्श्वनाथ

अपार्टमेंट के ई ब्लॉक में किराए से रह रहा था। 9 वीं कक्षा में पढ़ता था। पिता मिनरल वाटर कंपनी में मजदूरी करते है। पिता हंसराज ने बताया कि विशू दोपहर में अपार्टमेंट में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। खेलते समय बॉल गेट नम्बर तीन के पास चली गई। वहां हाईटेंशन लाइन का जॉइंट था। विशू नीचे झुककर बेट से गेंद निकालकर रहा था। उसी दौरान उसका सिर वायर के टच हो गया। मौके पर झुलस गया। धमाके की आवाज सुनकर लोग मौके पर आए। विशू बिजली के तार के नीचे पड़ा हुआ था, बेट भी झुलसा हुआ था।सोसायटी के लोगों ने फोन कर इसकी जानकारी दी।सूचना के 1 घंटे बाद तक केईडीएल के कर्मचारी मौके नहीं आए। हंसराज ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ वहां हाईटेंशन लाइन का जॉइंट है। जिसे दीवार के पास लोहे की जालियों से बांध रखा है। इस जगह को कवर्ड भी नहीं रखा, ना ही गेट या जाली लगा रखी। ये केईडीएल व सोसायटी की लापरवाही है। यहां खुले में तार छोड़ रखे है। नांता थाना एसएचओ नवल किशोर शर्मा ने बताया कि घटना दोपहर साढ़े 12 से 1 बजे के बीच की है। युवक क्रिक्रेट खेल रहा था। गेंद लेने साइट में गया था वहां बिजली के तार खुले थे। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही की शिकायत दी है। कानूनसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

कुश्ती एव जूडो के रोचक मुकाबले से खिलाडियों का चयन

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज- प्रदेश भर में खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज होने वाला है। राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित होने वाली 68 वीं खेलकूद प्रतियागिता के लिए जिले भर में स्कूल स्तर पर खिलाडियों के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई महात्मा गांधी राजकीय में छात्र-छात्राओं के जूडो एवं कुश्ती के 14 वर्ष व 17 वर्ष, 19 वर्ष के खिलाड़ि?यो के रोचक मुकाबले हुए खेल प्रभारी एवं शारीरिक शिक्षक धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया कि प्रधानाचार्य हेमलता चौधरी एवं भामाशाह अशोक खीचा, ललीत खीचा, भरत खीचा, राहूल खीचा, पुनित खीचा, आर्यन खीचा की उपस्थिति एवं आथित्य में प्रत्येक मुकाबले का शुभारम्भ करवाकर खेला का आनन्द लिया। भामाशाह अशोक खीचा एवं ललीत खींचा, भरत खीचा ने कुश्ती एवं जुडो खिलाडियों के लिए विद्यालय के लिए 25 ट्रैक शुट देने की घोषणा की। 14 वर्ष कुश्ती छात्र में प्रदीप सिंह, महिपाल सिंह, जैनिल, रोनक का अलग-अलग वजन में चयन हुआ वही जूडो में प्रकाश, मनोज कुमार, मनोज कुमार कलबी, वंश परिहार, फैजान, कुश्ती छात्रा में पिंकी कुमारी, मनस्विनि, किंजल कुमारी, शैलजा, जूडो छात्रा में प्रियंका कुमारी, खुशी फौजदार, प्रियंका डाँगी, पूजा चौधरी, कनिषा अग्रवाल का चयन हुआ। जो पिण्डवाड़ा में एक सितम्बर से आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं 17 वर्ष कुश्ती छात्र में कार्तिक कुमार, पियुष, राहुल गहलोत, मित सोनी, तनिष्क शर्मा, कुलदीप सिंह को चयन हुआ। 19 वर्ष कुश्ती में दर्पन परमार, मंयक सुथार, विशाल कुमार इसके अलावा 17 वर्ष जूडो में हर्षवर्धन सिंह, हितेष, लक्ष्य, वेदांश का चयन हुआ। इसके अलावा छात्रा जूडी 17 वर्ष में खुशबू, खुशी कुमारी, निविदिता कुमारी, आनिया सहित विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य गुलाब मीना, भामाशाह खीचा परिवार के प्रतिनिधि नीमा पुगलिया, पदम पुगलिया, दीपक रवीचा, चेतन खीचा, रमिला खीचा, सरिता खीचा के साथ ही विद्यालय परिवार के छगन भाटी, महेन्द्रपाल परमार, भंवरलाल हिन्डोनिया, संदीप मालवीय, आदित्य चौधरी, सुरजीत सिंह कविया, कुलदीप बांगड़ा, कुपाराम मीणा, गुलाब चन्द्र ने भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

दादावाड़ी वरिष्ठ अध्यापक व स्काउट सचिव आगलेचा को लॉयस क्लब ने सम्मानित किया

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज दादावाड़ी विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक व स्काउट सचिव स्थानीय संघ शिवगंज रमेशचन्द्र आगलेचा लॉयंस क्लब शिवगंज-सुमेरपुर द्वारा सम्मानित संघवी बाबूलाल अचलाजी जैन (तखतगढ़वाला) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दादावाड़ी शिवगंज में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक व सचिव राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ शिवगंज के सचिव रमेशचन्द्र आगलेचा को लॉयंस क्लब शिवगंज-सुमेरपुर द्वारा लॉयंस क्लब के सामाजिक सरोकार व सेवाकार्यों में स्काउट्स विद्यार्थियों के साथ हमेशा सेवा में तत्पर के कारण उनकी सेवाभावना व समर्पण के लिए लॉयंस क्लब शिवगंज-सुमेरपुर के सचिव लॉयन दीपक बंसल व क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन पंकज अग्रवाल द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ हनवंतसिह मेड़तिया लॉयंस क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों का आभार व्यक्त किया। प्राध्यापक बलवंतसिंह राठौड़ ने संवाददाता को बताया कि पूर्व में लॉयंस क्लब के संयोजक लॉयन नरेन्द्र जैन की प्रेरणा से भामाशाह सुमित परमार परिवार की ओर से दादावाड़ी विद्यालय के कक्षा प्रथम से आठवीं तक के विद्यार्थियों को 822 नोटबुक्स (अभ्यास पुस्तकाएं) वितरित की गई थी जिसकी मांग वरिष्ठ अध्यापक रमेशचन्द्र आगलेचा ने लॉयन नरेन्द्र जैन से की थी व इस पुनीत कार्य को अतिशीघ्र किया गया। लॉयन दीपक बंसल व लॉयन पंकज अग्रवाल ने शिवगंज ब्लॉक स्तरीय 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्काउट सचिव रमेशचन्द्र आगलेचा के नेतृत्व में स्काउट्स विद्यार्थियों द्वारा स्काउट पिरामिड व साहसिक गतिविधियां प्रदर्शन की प्रशंसा की। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रधानाचार्य डॉ मेड़तिया ने संवाददाता को बताया कि लॉयंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष लॉयन पंकज अग्रवाल को सेवाकार्यों के लिए शिवगंज ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य डॉ मेड़तिया ने वरिष्ठ अध्यापक रमेशचन्द्र आगलेचा की विद्यालय विकास व विद्यार्थी हित के सदैव तैयार रहने की सराहना की।

स्नेकलवर सोनी ने जन्म दिन पर एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम को अबोल प्राणीओ की सेवा के लिए कुछ दान देकर जन्म दिन मनाया

द पुलिस पोस्ट

शिवगंज स्नेक लवर अशोक सोनी ने आपने जन्मदिवस के उपलक्ष मे एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम को अबोल प्राणीयों की सेवार्थ 7100 /- - अक्षरे एकावन सौ रुपये की राशि भेंट की । एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम के संस्थापक महिपाल रावल ने बताया कि स्नेक लवर अशोक सोनी ने अपने जन्मदिन पर टीम को मुक प्राणीयों की सेवा मे इकहत्तर सौ रुपये की राशि टीम को समर्पित की , सोनी 18 वर्षों से सांपो व वन्यजीवों के संरक्षण के क्षैत्र निशुल्क सेवा दे रहे है , कई बार लोगो द्वारा सेवा शुल्क देने पर सोनी गौशाला को समर्पित करते आऐ है , साथ ही ब्रांड एम्बेसडर की उपाधि से विभूषित होने व जिला स्तर पर पंद्रह अगस्त को सम्मानित होने पर ओमप्रकाश कुमावत का भी महंत अयोध्या दास जी माराज के कर कमलों से बहुमान किया गया । स्नेक लवर सोनी ने बताया कि एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम वैसे काफी समय से अबोल प्राणियों की सेवा समर्पित भावना से कर रही है साथ ही अभी दो दिन पुर्व मे प्रसव पश्चात गाय का बच्चा 100 फिट गहरे कुऐ मे गिर गया था जिसे मध्य रात्रि मे सुचना मिलने पर अपने प्राणों की परवाह किये बगेर सकुशल बाहर निकाला । जिससे अभिभुत हो सोनी ने जन्मदिन पर रेस्क्यू टीम का महंत अयोध्या दास जी माराज के कर कमलों से बहुमान करा मुक प्राणियों की सेवार्थ 7100 रुपये समर्पित किये। महंत अयोध्या दास जी माराज , ब्रांड एम्बेसडर ओमप्रकाश कुमावत एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम

के संस्थापक महिपाल रावल , सेवानिवृत्त वनपाल पन्नालाल , पार्षद व समाज सेवी राजेश अहीर , रेस्क्यूअर दिनेश यादव व करण यादव , स्नेक लवर अशोक सोनी , विलास मराठा , एनिमल हेल्प रेस्क्यू टीम से रोशन सोनी , रुद्र नानावटी , साहील सोनी , राज देवडा , चंद्रवीर परिहार , राकेश सोलंकी , प्रियांशु कुमावत , प्रेम माली , राजु बोराणा , हनुमान सोनी आदि का सानिध्य रहा ।

सौ फीट गहरे संकरे कुएं में गिरे बछड़े का गोसेवकों ने किया सफल रेस्क्यू

बरलूट वास के एक जर्जर मकान में गाय ने दिया था बछडे को जन्म, कुछ समय बाद बछडा खुले कुएं में गिर पडा

पालिकाध्यक्ष का वार्ड मे खुल्ला पडा था यह कुआँ इसमे सैकड़ो जिव जन्तु है ईस प्लोट मे बडे पीपल के पेड भी खडे है

शहर मे चर्चा है गाय माताजी ने वैष्णव को महादेव के दर्शन करवाए यहा पर मंदिर बनाने की मांग की

मां की ममता का अनुठा उदाहरण देखने को मिला, बछडे को बचाने के लिए अपने मालिक को लेकर उसी मकान तक पहुंची गाय

द पुलिस पोस्ट

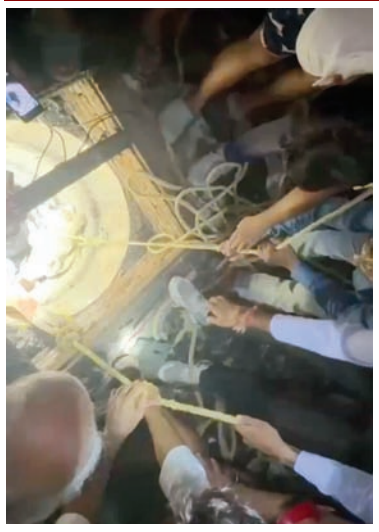

शिवगंज। मां की ममता का एक अनुठा उदाहरण सोमवार को यहां देखने को मिला है। कुएं में गिरे अपने नवजात को बचाने के लिए गाय प्रसव पीडा में होने के बावजूद मालिक के घर तक पहुंची और उसे फिर से उसी स्थान तक लेकर आई जहां उसका बच्चा कुएं में गिरा था। मालिक जब उस स्थान पर पहुंचा तो घर में बने एक कुएं में बछडे की आवाज सुन गोसेवकों को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे गोसेवकों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे जीवित बाहर निकालने में सफलता हासिल कर ली। जानकारी के अनुसार रविवार की रात्रि में शहर के बरलूट वास में खंडहरनुमा एक मकान के अहाते में एक गाय ने प्रसव पीडा के दौरान एक बछडे को जन्म दिया था। वहां अंधेरा होने की वजह से कुछ समय बाद बछडा चलता हुआ घर में ही बने एक संकरे खुले कुएं तक पहुंच गया और वह संभल पाता उससे पहले वह उसमें गिर पडा। अपने बच्चे को कुएं में गिरा देख मां ने उसे बचाने के लिए वह प्रसव पीडा के बावजूद भागती हुई अपने मालिक के घर पहुंची और रंभाने लगी। पहले तो मालिक कुछ समझ ही नहीं सका कि आखिर गाय इतना क्यों रंभा रही है। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके प्रसव हो गया है और साथ में बच्चा नहीं है तो वह गाय के साथ निकल पडा। गाय अपने मालिक को लेकर बरलूट वास उसी स्थान पर पहुंची जहां उसका बच्चा कुएं में गिरा था। वह कुएं के पास खडी होकर रंभाने लगी तो मालिक को अंदेशा हुआ कि बछडा कहीं कुएं में तो नहीं गिर पडा है। इसी दौरान कुएं के भीतर से बछडे के रंभाने की आवाज आने लगी तो वह घबरा गया। गाय मालिक की ओर से इसकी सूचना शंकर वैष्णव को दी। वैष्णव की ओर से गोसेवक महिपाल रावल को सूचना दिए जाने पर रावल अपनी टीम और रेस्क्यू उपकरणों के साथ बरलूट वास पहुंचे तथा लाइट की व्यवस्था कर बछडे को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए। चूंकि कुंआ संकरा था इस वजह से एक ही व्यक्ति भीतर जा सकता था। जिस वन्यजीव प्रेमी दिनेश यादव ने भीतर जाने का फैसला लिया। करीब दो घंटे के प्रयासों के बाद गोसेवकों की टीम ने बछडे को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल उसे उसकी मां के पास छोड दिया। अपने बच्चे को जीवित देख मां का प्यार अपने बच्चे के लिए उमड पडा। इस जोखिम भरे कार्य को अंजाम देने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों ने गोसेवकों का आभार प्रकट किया। इस कार्य में गोसेवक प्रदीपसिंह, शंकर वैष्णव, गोविन्द वैष्णव, श्याम वैष्णव, सुरेश रावल, राजेन्द्र शर्मा सहित एनिमल हैल्प रेस्क्यू टीम के कई सदस्य मौजूद थे। गौमाताजी ने अपने बछड़े को बहार निकालने के लिए पीपलेश्वर महादेव के दर्शन करवाए महादेव संयम वहा पर गाय के बछड़े की रक्षा कर रहे थे सैकड़ो नाग और बिच्छु है वहा पर भगवान महादेव की मर्जी से यहा पर मकान मालिक मकान नही बना रहे थे मकान मालिक को भी मंदिर बनाने की सद्बुद्धि देगा क्यू की बरलूट वास मे मंदिर नही है अब मंदिर बनेगा वैष्णव ने भगवान महादेव के दर्शन हुए है राञी मे अब वैष्णव ही मंदिर बनाने की कार्रवाई करेंगे। गाय माताजी व बछडे का भी मंदिर बनाया जाएगा ।

आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 80वीं जयंति पर पालिका टाउन हॉल में स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृंदाजली दी गई

द पुलिस पोस्ट

शिवगंजः आज मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की 80वीं जयंति पर पालिका टाउन हॉल में स्व. राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रृंदाजली दी गई। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री वजींगराम घांची ने अपने विचार रखते हुये बताया कि आज देश सदभावना दिवस मना रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत के महान सपूत थे उन्होने करोडो भारतीयों में आशा की किरण जगाई एवं अपने अभूतपूर्व योगदान से भारत को 21वीं सदी में पहुँचाया है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री प्रकाशराज मीना ने बताया कि राजीव गांधीजी ने मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष की साथ ही पंचायती राज को मजबूत करना, दूरसंचार, आईटी क्रांति, नई शिक्षा नीति जैसे उनके कई सुखद कदम देश में परिवर्तन लायें। नगर अध्यक्ष श्री मदन माली ने भी विचार रखें। इस मौके पर दलपतसिंह इन्दा, राजेन्द्र माली, ओमप्रकाश सुथार, महेन्द्र वाघेला, छोगाराम जरीवाला, अरविन्द पराशिया, चम्पालाल तिरगर, राहुल चांवरिया, रमेशकुमार मुकेश मीणा इत्यादि मौजूद थे।

महोदया के बंगले पर दिन को जगमगाती रोड़ लाइटें

परिषद की लापरवाही का नतीजा जनता को भुगतना पड रहा है।

द पुलिस पोस्ट

सिरोही, यूं तो शहर में कई गली मोहल्लों कोलोनीयो में रोड़ लाइटें बंद होने की शिकायते करते आम लोगों को अक्सर देखा जाता रहा है लेकिन जिला कलेक्टर महोदया के बंगले के बार अन्दर दिन को भी रोड़ लाइटें जगमगाती नजर आ रही है हो सकता है किसी तकनीकी खराबी के कारण रोड़ लाइटें जिला अधिकारी के आवास पर दिन को जलती नजर आ रही हो किसी गली मोहल्लों कोलोनीयो में दिन में जलती रोड़ लाइट की सूचना भले संम्बन्धित विभाग अधिकारी के पास समय पर नहीं पहुंचे तो समझ में आ सकता है लेकिन एक जिले के शीर्ष अधिकारी के बंगले पर दिन में रोड़ लाइटें जगमगाती रहें आखिर रोड़ लाइटों का भुगतान तो आम जनता को ही करना है नगर परिषद सिरोही के सभापति व आयुक्त बताएं किन किन अधिकारियों के बंगलों पर कितनी रोड़ लाइटों से जगमगाहट होते हैं और बंगलों के अन्दर रोड़ लाइटें लगाने का कानून में क्या प्रावधान है!

भारत बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट

जिला कलक्टर तथा एसपी ने संगठनों के साथ की बैठक,शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील

अफवाह एवं भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर रखी जा रही है सतत निगरानी, आपसी सौहार्द्ध एवं शांतिपूर्ण रूप से रखें अपनी बातः जिला कलक्टर

पुलिस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध, कानून व्यवस्था की करें पालनाः एसपी

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, जिले में 21 अगस्त को भारत बंद के आह्वान के सम्बंध में अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा प्रस्तावित भीलवाड़ा बंद को देखते हुए जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारिक संगठनों, अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, एडीएम सिटी वंदना खोरवाल सहित प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला कलक्टर ने कहा कि भारत बंद के आह्वान में जिले में भी बंद को लेकर सम्बंधित संगठन कानून व्यवस्था की पालना करते हुए अपनी बात रखें। शांतिपूर्ण तरीके से सभी वर्गों में आपसी समन्वय बनाये रखकर ज्ञापन देने आते समय मार्ग में कानून का पालन करें। उन्होंने किसी भी तरफ की भ्रामक सूचनाओं को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं करने तथा ऐसी सूचनाओं को जिला प्रशासन व पुलिस के ध्यान में लाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि बंद समर्थक सभी संगठन रैली में किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्रों, लाठी, डंडों को लेकर नहीं चलेंगे। उन्होंने किसी जाति, धर्म, वर्ग की भावनाओं को आहत करने वाले नारों का उपयोग नहीं करने, डीजे

अन्य ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करने वाले गीतों, भाषणों का प्रसारण नहीं करने के निर्देश दिए। बंद के दौरान जनहित में समस्त आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा के अन्तर्गत मैडिकल स्टोर, एम्बूलेंस, हॉस्पीटल, पेयजल, शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक परिवहन, पैट्रोल पम्प, रेल सेवा इत्यादि को किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जायेगी।जिला कलक्टर ने सभी व्यापारिक संगठनों को भी आह्वान किया कि वे बंद के दौरान कानून व्यवस्था की पालना करते हुए संगठनों के द्वारा लिए गए निर्णय के तहत कार्य करें। उन्होंने सभी व्यापारिक संगठनों, नागरिक संगठनों को आश्वस्त किया कि प्रशासन, पुलिस हमेशा सभी नागरिकों के साथ कानून व्यवस्था के लिए है। आपसी सौहार्द्ध के लिए वे समन्वय से कार्य करते हुए नियमों की पालना करें। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बंद समर्थक सभी संगठन अपनी बात रखते समय कानून व्यवस्था के तहत शांति के साथ अपनी बात रखें। रैली में एकत्रित होने से लेकर ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट आने तक किसी भी सार्वजनिक या व्यक्तिगत सम्पत्ति को प्रभावित किये बिना धैर्य के साथ अपना कार्य करें। उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रशासन सभी नागरिकों की सुरक्षा एवं हित के लिए है, रैली में असमाजिक तत्व प्रवेश नहीं करें। संगठनों की ओर से वॉलियंटर्स को रैली में व्यवस्था बनाये रखने के लिए तैनात कर उन्हें जिम्मेदारी दें। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निरंतर निगरानी रखी जा रही है, किसी भी व्यक्ति द्वारा भ्रामक एवं डीप फेक फोटो, वीडियो अपलोड या शेयर किये जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने सभी संगठनों को आह्वान किया कि भ्रामक एवं अफवाह की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन अथवा पुलिस के ध्यान में लायें जिससे उसकी सत्यता का पता लगाया जा सके। उन्होंने रैली के दौरान लाठी, डंडे, अस्त्र, शस्त्रों को साथ लेकर नहीं चलने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यापारिक संगठनों को स्वैच्छिक रूप से बंद के दौरान नियमों का पालन करने के निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस हर कदम पर आमजन की सुरक्षा के लिए है।

एससी एसटी वर्ग के पदाधिकारियों ने दिया आश्वासन

एससी एसटी वर्ग के पदाधिकारियों ने बैठक में कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था जिस तरह से पहले की तरह कायम है उसी तरह से कायम रखी जाएगी। सभी संगठनों ने प्रशासन को आश्वस्त किया है कि प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा।

सामयिकः निरंतरता की ओर भारत

अवधेश कुमार

प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री के लिए केवल अपने किए गए कार्यों के विवरण के प्रस्तुति का मंच नहीं बल्कि भविष्य के सपने और उसके पूरा करने का आत्मविश्वास दिलाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। वास्तव में 78 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन से उन्होंने कुल मिलाकर भारत और भारत के बाहर भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भारत समग्र रूप में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और इसे निर्धारित समय पर प्राप्त करके रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सभी 11 स्वतंत्रता दिवस संबोधनों को देखें तो आपको उसमें देश को लेकर किसी स्तर पर निराशा या नकारात्मकता की झलक नहीं दिखाई देगी। लाल किला से उन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा कि स्वतंत्रता दिवस का संबोधन लोगों के अंदर देश के लिए जिम्मेदारीपूर्वक काम करने और हर परिस्थिति में साहस व संकल्प बनाए रखने की प्रेरणा दें। 15 अगस्त , 2024 के लाल किले के संबोधन पर ही दृष्टि दौड़ाएं तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर भाजपा के बहुमत से पीछे रह जाने और गठबंधन सरकार की विवशताओं का रंच मात्रा भी प्रभाव है। पूरा भाषण देश को यह विश्वास दिलाने पर केंद्रित रहा कि सरकार भारत को हर दृष्टि से विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने के लिए कमर कसकर काम कर रही है और आम लोगों का भी सहयोग प्राप्त है जिसे और सशक्त करने की जरूरत है। मोदी के आलोचकों की दृष्टि में उनके भाषणों में सपनों और कल्पनाओं का ऐसा भावुक शब्द चित्रण होता है जिसमें लोग मोहित हो जाते हैं। सच यह है कि उसी के आधार पर देश को किसी काम के लिए या स्वयं व्यक्तिगत जीवन में भी सफल होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री के लिए केवल अपने किए गए कार्यों के विवरण के प्रस्तुति का मंच नहीं बल्कि भविष्य के सपने और उसके पूरा करने का आत्मविश्वास दिलाने का सबसे बड़ा अवसर होता है। वास्तव में 78 में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन से उन्होंने कुल मिलाकर भारत और भारत के बाहर भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि भारत समग्र रूप में विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है और इसे निर्धारित समय पर प्राप्त कर-के रहेगा। वर्तमान वैश्विक ढांचे में विकसित राष्ट्र की परिभाषा क्या है? अर्थव्यवस्था के वैश्विक मानकों पर खरा उतरना, शिक्षा के क्षेत्र में मूलतः सामान्य, तकनीकी एवं प्रोफेशनल संस्थाओं और उनके प्रदर्शनों को विश्व मानकों के अनुरूप लाना, रक्षा क्षेत्र में न केवल ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होना बल्कि विश्व बाजार में सामग्रियों के विक्रय की प्रतिस्पर्धा में टिकना, आम लोगों का जीवन स्तर का निर्धारित मानक प्राप्त करना आदि आदि। प्रधानमंत्री के संबोधन का बहुत बड़ा भाग इसी पर केंद्रित था कि कैसे हमने अर्थव्यवस्था को विश्व मानकों के अनुरूप प्रगति के पथ पर लाया है और भारत की गिनती दुनिया की 5 बड़ी

अर्थव्यवस्थाओं में हो रही है जो शीघ्र तीसरे स्थान पर पहुंच जाने वाली है। उन्होंने विश्व भर के निवेशकों को विश्वास दिलाया कि हमने निवेश एवं कारोबार की दृष्टि से आर्थिक, कानूनी, वित्तीय, व्यावसायिक आदि क्षेत्र में सुधार से ऐसे ढांचा निर्मित कर दिए हैं जिसमें आपके लिए परेशानी और जोखिम के लिए जगह न के बराबर है। आगे भी करते रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उन्होंने स्पष्ट या संकेतों के द्वारा बताया कि कोई भी देश अपनी सभ्यता-संस्कृति और पहचान के साथ विकसित बनेगा तभी वह लंबे समय टिकेगा। इसमें शिक्षा व्यवस्था सबसे महत्तवपूर्ण है। मातृभाषा में शिक्षा मोदी सरकार की शिक्षा नीति में का महत्तवपूर्ण स्तंभ है। केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, सूचना तकनीक आदि के लिए भी इसमें स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का लक्ष्य है। जो प्रतिभाएं अंग्रेजी न जानने के कारण कुम्हला कर नष्ट हो जाती हैं उनके पूरी संभावनाओं के साथ खिलने का इसमें अवसर है। इसकी उन्होंने पूरी चर्चा की। ध्यान रखिए हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा सपना मातृभाषा के आधार पर शिक्षा एवं भारत का निर्माण था। हालांकि कांग्रेस का मुख्य नेतृत्व कुछ प्रमुख अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के हाथों में होने के कारण स्वतंत्रता के बाद यह साकार नहीं हो सका, लेकिन मोदी सरकार नई शिक्षा नीति के साथ धीरे-धीरे पूरे ढांचे में बदलाव की कोशिश कर रही है। जिन लोगों ने शिक्षा नीति पर काम किया है या उसे साकार करने की कोशिशें देख रहे हैं उन्हें विश्वास है कि यद्यपि इस ढांचे में जबरदस्त बाधाएं हैं, लेकिन सफलता मिलेगी। किसी भी समाज और राष्ट्र के संपन्न होने में उसका कानूनी ढांचा और न्याय प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून आपके अनुरूप, आपके समझने लायक और न्याय प्रणाली कम खचीर्ली तथा वास्तविक न्याय दिलाने वाली हो तो वह देश कुंठाओं से ऊपर अपनी कानूनी और न्यायिक समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ता रहता है। प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में 1400 कानूनों को खत्म करने तथा नई न्याय संहिता की चर्चा की। वैसे अभी इसका असर देखा जाना शेष है। एक बार बदलाव का क्रम बढ़ता है तो सुधार की संभावनाएं पैदा होने लगती है।

भारत जैसे देश में लोगों के लिए समान नागरिक कानून नहीं हो तो न संपूर्ण प्रगतिशील समाज का निर्माण होगा और न एक बहुत बड़ा वर्ग विकास की गाथा में अपनी भूमिका निभा सकेगा। सामान्यता समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोर्ड को भाजपा या आरएसएस के एजेंडे के रूप में देखा जाता है। हमारे संविधान निमार्ताओं ने भी पंथ, मजहब, नस्ल से ऊपर उठकर सबके लिए समान समान नागरिक संहिता का लक्ष्य घोषित किया था। वोट की राजनीति या मुस्लिम समुदाय को लेकर आत्मघाती विचारधारा के कारण यह लक्ष्य साकार नहीं हो सका। इसके बगैर आप विश्व में सम्मानित विकसित और भारत को भारत के रूप में प्रभावी देश नहीं बना सकते। इसलिए प्रधानमंत्री ने अब सांप्रदायिक नागरिक कानून से बाहर निकाल कर सेक्यूलर नागरिक कानून की बात की है। जो सबके लिए समान कानून होगा वही सेक्यूलर होगा।

ऐसा नहीं है तो वास्तव में सांप्रदायिक कानून ही है। स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इसके उल्लेख और व्याख्या का मतलब है कि प्रधानमंत्री ने देश को स्पष्ट कर दिया है कि हम सब मिलकर इसका मन बनाएं और देश उसकी ओर बढ़े, क्योंकि संपूर्ण समाज की प्रगति और भारत की सुख, शांति समृद्धि के साथ खड़ा होने के रास्ते की बहुत बड़ी बाधा है। यही भारतीय दृष्टि हमारे कृषि क्षेत्र के संदर्भ में भी है। उन्होंने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया। इस तरह देखें तो निष्कर्ष आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन से दिखाए गए सपने और संभावनाएं अगर साकार रूप लेंगे तो भारत आने वाले सैकड़ों वषाड्ड तक सुखी, शांत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व का दिशाझ्रदर्शन करता रहेगा।

संपादकीय

समयानुकूल हस्तक्षेप

देश की सर्वोच्च अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेड़िकल कॉलेज व अस्पताल में हुए कथित बलात्कार व हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश ड़ीवाई चंद्रचूड़.की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। इस दुखद घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। निजी व सरकारी चिकित्सकों के देशव्यापी हड़ताल व प्रदर्शनों को लेकर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुरक्षा उपाय सुझाने के लिए समिति गठित करने का वादा किया गया। दोषियों की कड़ी से कड़ी सजा देने की चौतरफा मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भी मामले को फास्ट ट्रैक अदालत में ले जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने दोषियों को फांसी दिये जाने की भी बात की। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान न होने व अपर्याप्त आश्वासनों के चलते नाराज चिकित्सकों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नये आदेश जारी किए गए। जिनके अनुसार, सभी राज्यों को कानून व्यवस्था की जानकारी गृह मंत्रालय को हर दो घंटे में देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस मामले में लोगों के बढ़ते आक्रोश व मृतका को न्याय दिलाये जाने की पहल है। यदि यह गैंगरेप है तो सभी दोषियों को कठघरे में लाना तथा दोषियों को बचाने वालों का खुलासा होना भी जरूरी है। खबरों के अनुसार अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस हत्या के पीछे मानव अंगों की तस्करी व सेक्स रैकेट भी हो सकता है। जिस तरह सबूतों से छेड़छाड़.की गई, वह भी संदेहास्पद है। दूसरे बनर्जी द्वारा सीबीआई जांच से पूर्व स्थानीय पुलिस को पांच दिन का वक्त देना भी संदेह से परे नहीं है। यह घटना दिल्ली में हुए निर्भया कांड़ से भी भीषण प्रतीत हो रही है। दोषियों की मंशा और बलात्कारियों-हत्यारों की पहचान बेहद जरूरी है। इन्हें बचाने का प्रयास करने वालों का पदार्फाश तभी मुमकिन है, जबकि निष्पक्ष जांच संभव हो। सबसे बड़ी अदालत का जनहित के मामलात में हस्तक्षेप गंभीर अपराधों पर होने वाली राजनीति पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है। साधारण दर्जी पिता की होनहार बेटी के साथ हुई दरिंदगी का असर देश के उन तमाम पालकों पर पड़.रहा है, जो बच्चियों को पढ़ाने और काबिल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बेटी को सिर्फ पढ़ाना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें सुरक्षा भी देना है, जिसमें हम बुरी तरह असफल हैं।

चिंतन-मनन

नर या नारायण कौन थे राम

श्रीराम पूर्णतः ईश्वर हैं। भगवान हैं। साथ ही पूर्ण मानव भी हैं। उनके लीला चरित्र में जहां एक ओर ईश्वरत्व का वैचित्रमय लीला विन्यास है, वहीं दूसरी ओर मानवता का प्रकाश भी है। विश्वव्यापिनी विशाल यशकीर्ति के साथ सम्यक निरभिमानिता है। वज्रवत न्याय कठोरता के साथ पुष्यवत प्रेमकोमलता है। अनंत कर्ममय जीवन के साथ संपूर्ण वैराग्य और उपरति है। समस्त निषमताओं के साथ नित्य सहज समता है। अनंत वीरता के साथ मनमोहक नित्य सौंदर्य है। इस प्रकार असंख्य परस्पर विरोधी गुणों और भावों का समन्वय है। भगवान श्री राम की लीला चरित्रों का श्रद्धा भक्ति के साथ चिंतन, अध्ययन व विचार करने पर साधारण नर नारी भी सर्वगुण समन्वित एवं सर्वगुण रहित अखिल विश्व व्यापी, सवार्तीत, सर्वमय श्रीराम को अपने निकटस्थ अनुभव कर सकते हैं। श्री राम में नर और नारायण तथा मानव और ईश्वर की दूरी मिटाकर भगवान के नित्य परिपूर्ण स्वरूप का परिचय मिलता है। भगवान पुरुषोत्तम ने श्री राम के रूप में प्रकट होकर मानवीय रूप में सांसारिक लोगों के दिलो दिमाग पर नित्य प्रभुत्व की प्रतिष्ठा कर समस्त भारतीय संस्कृति को आध्यात्म भाव से ओतप्रोत कर दिया है। रामचरितमानस महाकवि तुलसीदास की अमर कृति है। यह एक ऐसा सर्वोपयोगी आदर्श प्रदर्शित करने वाला पवित्र धर्मग्रंथ है। जिसने मयार्दा पुरुषोतम भगवान श्रीराम को समस्त नर नारियों के हृदय में परम देवत्व रूप के साथ अत्यंत आत्मीय रूप में प्रतिष्ठात किया है। इसने शिक्षित अशिक्षित? आबाल वृद्ध शास्त्र पुरुष सभी प्रकार के जीवन को श्रीराम के प्रति भक्ति तथा प्रेम के दिव्य, मधुर सुधारस से अभिषिक्त कर अपना अद्भुत प्रभाव विस्तार किया है। श्रीरामचरितमानस के श्रीराम सर्वसद्गुण संपन्न मयार्दारक्षक परम आदर्श शिरोमणि होने के साथ ही स्वमहिमा में स्थित महामानव है। श्रीरामचरित मानस के श्रवण, मनन तथा चिंतन से अत्यंत विष्यासक्त, असदाचारी कठोर हृदय मानव भी पवित्र विचार परायण एवं सदाचारी होकर निर्मल प्रेम भक्ति की रसधारा में सराबोर होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस ग्रंथ के सभी पात्र आदर्श चरित्र से परिपूर्ण हैं। इसमें गुरु शिष्य, माता पिता, भ्राता पुत्र स्वामी सेवक, प्रेम सेवा, क्षमा, वीरता, दान, त्याग, धर्मनीति आदि संपूर्ण आदर्शों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं।

लेटरल भर्ती का विरोध देख सरकार ने पीछे खींचे कदम

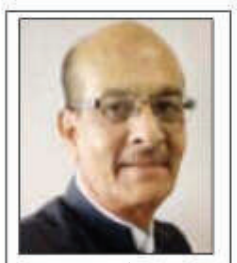

सनत जैन

केंद्र सरकार द्वारा यूपीएससी के पदों पर बिना आरक्षण लैटरल भर्ती 2018 के बाद से लगातार किए जा रही है, लेकिन इस मामले ने 2024 में तूल पकड़ लिया है। 2018 से लेकर अभी तक केंद्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों में विशेषज्ञों के नाम पर लैटरल भर्ती समूह में करती चली आ रही है। इस बार केंद्र सरकार द्वारा 45 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। पिछले 6 वर्षों में लगभग 200 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। उसके बाद से आरक्षण मुद्दे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मोदी सरकार द्वारा 2018 के बाद से लैटरल नियुक्तियां समूह में की जा रही हैं। अभी तक यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से इनका चयन होता था। 15-20 वर्ष की सेवा के पश्चात, चयनित अधिकारी उप सचिव, संयुक्त सचिव और सचिव पद पर पहुंचते थे। अब सीधे ही भर्ती विभिन्न मंत्रालयों में उपसचिव, संचालक और संयुक्त सचिव के रूप में की जा रही है। एक तरह से यह नियमों का दुरुपयोग है। संवैधानिक प्रावधानों का पालन भी सरकार नहीं कर रही है। जिसके कारण यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी इस तरह से की जा रही नियुक्तियों का विरोध शुरू कर दिया है। जनता दल यू ने इस तरह की भर्ती पर गंभीर चिंता जताई है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की नियुक्तियों में आरक्षण का पालन किया जाना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इसे संविधान विरोधी बताते हुए आरक्षण खत्म करने की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है, सरकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को प्रमुख पदों पर सीधे नियुक्त कर रही है। इस तरह की नियुक्तियों से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के हितों का नुकसान हो रहा है। संविधान में जिस तरह से कार्यपालिका में अधिकारियों का चयन किया जाना है, उसका पालन भी सरकार नहीं कर रही है। सरकार में पूंजीपतियों का सीधा हस्तक्षेप बढ़ रहा है। लैटरल नियुक्तियों में उन लोगों की भर्ती हो रही है, जो कारपोरेट जगत से हैं। वे सीधे सरकारी सेवा के महत्वपूर्ण पदों पर आ रहे हैं। इनकी नियुक्ति विशिष्ट तरीके से की जा रही है। कांटेक्ट पर नियुक्ति होने के कारण यह कभी भी छोड़ कर जा सकते हैं। इन पर जिम्मेदारी भी तय नहीं की जा सकती है। सेबी में माधवी बुच को पहले डायरेक्टर और फिर अध्यक्ष बनाने का मामला भी विवादों में आ गया है। जो खुलासे हुए हैं, वह बड़े आश्चर्यचकित करने वाले हैं। सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि औद्योगिक समूहों के अधिकारियों को पिछले दरवाजे से सरकारी पदों पर नियुक्ति की जा रही है। यह अधिकारी औद्योगिक समूह के हित में नीतियां बनाते हैं। संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार जब किसी निर्णय में फंसने लगती है तो इस स्थिति में सरकार कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़कर बचने का रास्ता बनाती है। सरकार की ओर से यही प्रयास किया गया है। इस तरह की नियुक्तियां 50 वर्षों से हो रही हैं। 1976 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लैटरल एंट्री के माध्यम से वित्त सचिव बनाया गया था। राजीव गांधी की सरकार ने सेम पित्रोदा को नॉलेज कमीशन का अध्यक्ष बनाया था। विमल जालान को मुख्य आर्थिक सलाहकार रिजर्व बैंक बनाया गया था। 2009 में कौशिक बसु को केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। रघुराम राजन को भी वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। मोंटेक सिंह अहलुवालिया 2004 से 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे। 2009 में नंदन नीलकेणी को भी यूआइडीएआइ का मुखिया बनाया गया था। पिछले 50 वर्षों में केंद्र सरकार में विशेषज्ञ के रूप में जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी, उनकी संख्या वर्तमान की तुलना में बहुत कम है। वित्त और तकनीकी के जानकार उस समय देश में बहुत कम विशेषज्ञ थे। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानकारी और विशेषज्ञता रखते थे। पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा उप सचिव, सचिव और संचालक स्तर पर जो नियुक्तियां की जा रही हैं। उसमें हमेशा से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या भारतीय सेवा के अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। लैटरल भरती का मुद्दा अब गरमा गया है। इसे उच्च पदों पर आरक्षण खत्म करने से लेकर जोड़ा जा रहा है। सरकार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, ऐसी स्थिति में एनडीए सरकार में दरार पड़ सकती है। केंद्र सरकार पहले ही जाति आरक्षण और संविधान को खत्म करने के आरोप में बुरी तरह से घिरी हुई है। बजट सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्रालय में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर वित्त मंत्री को सदन के अंदर घेरा था। इस बार केंद्र में गठबंधन की सरकार है। आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले पर यदि उसके सहयोगी दल उसका साथ नहीं देंगे, तो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। सरकार के अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। जिसके कारण देश में राजनीतिक हलचल बड़ी तेजी के साथ बढ़ गई है। लगातार हुए विरोध का नतीजा ही कहेंगे कि अब केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री को लेकर अपने कदम वापस पीछे खींच लिए हैं। दरअसल लेटरल भर्ती मामले को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच में ही कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए संघ लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने के लिए कहा है। इसमें उल्लेख किया गया है कि चूंकि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस ले लिया जाए। इससे यह तो स्पष्ट है कि गठबंधन वाली यह सरकार ज्यादा विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती है, यदि ऐसा हुआ तो कुर्सी जाने का खतरा सदा बना रहेगा। ऐसे में अपने कदम वापस ले सरकार ने लोगों की नाराजगी से बचने का काम किया है।

बलात्कार की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक

मुस्ताअली बोहरा

ये कैसा विकसित भारत.....

ये कैसी विडम्बना है कि जहां एक तरफ लाल किले की प्राचीर से देश में न्यायिक सुधार, 2047 में विकसित भारत और महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा की बात की जा रही थी तो दूसरी तरफ देश की बेटियां न्याय की मांग करते हुए आंदोलन कर रहीं थी। जश्न-ए-आजादी के बीच महिलाओं का ये आंदोलन कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कब तक इसी तरह बलात्कार होते रहेंगे, कब तक ऐसे दरिंदे खुलेआम घूमते रहेंगे, कब तक महिला सुरक्षा को लेकर जबानी जमा खर्च होता रहेगा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने हर किसी झकझोर दिया है। इसको लेकर देश भर गुस्सा है। विपक्ष से लेकर सेलिब्रिटीज, राजनेता और आम आदमी हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर आजादी के इतने बरसों बाद भी महिलाएं सुरक्षित और आजाद क्यों नहीं हैं। कोलकाता के रेप-मर्डर मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। आपराधिक आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि देश में बलात्कार चैथा सबसे आम अपराध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 32033 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे या ये भी कहा जा सकता है कि हर रोज औसतन 88 मामले दर्ज

हुए। इसके अलावा नाबालिगों के साथ उत्पीड़न और बलात्कार की घटनाएं भी सामने आतीं रहतीं हैं। ब्यूरो की इन आंकड़ों से जाहिर है बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हुईं हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी बलात्कार की घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं।

खैर, कोलकाता की घटना के बाद एक फिर डॉक्टर आंदोलित हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। इन डॉक्टरो को देश के अन्य राज्यों के डॉक्टरो का भी समर्थन मिल रहा है। कोलकाता में डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रहीं हैं। डॉक्टरो का कहना है कि उन्हें माकूल सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। सभी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इस मामले में जल्द से जल्द न्याय हो। हड़ताली डॉक्टरों की एक प्रमुख मांग यह है कि हेल्थकेयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए देश में एक नया केंद्रीय कानून या सेंट्रल हेल्थकेयर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। साथ ही इस घटना की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सख्त कदम उठाए जाने की बात कही है। देश भर के डॉक्टर कोलकाता के डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं। डॉक्टरो की चिंता बेवजह नहीं है। हालांकि, जहां तक केंद्रीय कानून की मांग है तो पहले ये देखना होगा कि क्या बलात्कार की इस तरह की घटनाओं के पीछे कानून का कमजोर होना है या फिर किसी कड़े कानून की कमी इसकी वजह है। वैसे, ज्यादातर राज्यों में मेडिकेयर सर्विस पर्सन एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टिट्यूशंस (प्रिवेंशन ऑफ वॉयलेंस एंड डैमेज-लॉस टु प्रॉपर्टी) एक्ट पहले से ही लागू है। मगर इन राज्यों में भी इसके तहत दर्ज मामलों में दस फीसदी ही आरोप तय होने के बाद अदालत पहुंच सके। तो ये माना जा सकता है कि असल समस्या कानून की कमी नहीं बल्कि उस पर सख्ती से अमल है। बहरहाल, अस्पताल में लेडी डॉक्टर ही नहीं बल्कि पुरूष डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ और दिगर स्वास्थ्य कर्मी भी हमलों का शिकार होते रहते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं हैं अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा भी बड़ा मसला है। अस्पतालों में भर्ती महिला मरीजों भी यौन हमलों की खबरें आतीं रहतीं हैं। देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को लेकर व्यापक जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है। मंहगी शिक्षा और मंहगी दवाएं तथा अस्पतालों में इलाज और जांच के नाम पर होने वाला खर्च भी चर्चा का विषय है। कतिपय अस्पतालों में मेडिसिन और सर्जिकल आइटम की सप्लाई के गोरखधंधे, कमीशनखोरी, और इससे जुड़े रैकेट के सक्रिय होने की बात तो सब जानते हैं लेकिन कोलकाता के इस मामले में सेक्स रैकेट और ड्रग्स का एंगल भी सामने आया है। बहरहाल, सीबीआई जांच के बाद और भी चैकाने वाले खुलासे हो सकते हैं लेकिन इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। डॉक्टरो पर हमलों के साथ ही मरीजों पर भी वित्तीय हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाया जाना जरूरी है।

जवाई क्षेत्र की पहाड़ियों पर व पास की फौरेसट की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाया जाएंगा जहाँ टाइगर रिजर्व जगह पर अतिक्रमण हो गया है कब कारवाई होगी

सरकारी जमीन का ऐलोटमेंट किया है उसे खारिज करना चाहिए जिसने करवाया उसके विरुद्ध कारवाई करनी चाहिए

एन- जी -टी भोपाल ,मध्यप्रदेश मे हुआ दर्ज प्रकरण पर होगी कारवाई

कामबेश्वरजी, कोलर की पहाड़ियों जवाई कन्वॅजन एरिया मे सैकडों जंगली जानवरों के जीवन को खतरा बना हुआ है

मोदी सरकार व भंजनलाल शर्मा सरकार जानवरों की रक्षा करने मे करोडों रुपए खर्च कर रहे हैं पर शिवगंज सुमेरपुर अधिकारी क्यू नही रक्षा करनी चाहते है

बडी बडी होटलों व रिसोर्ट व टेंटो की होटले बनाकर जानवरों के जीवन को खतरों मे डाल रहे है सबको धन चाहिए

द पुलिस पोस्ट

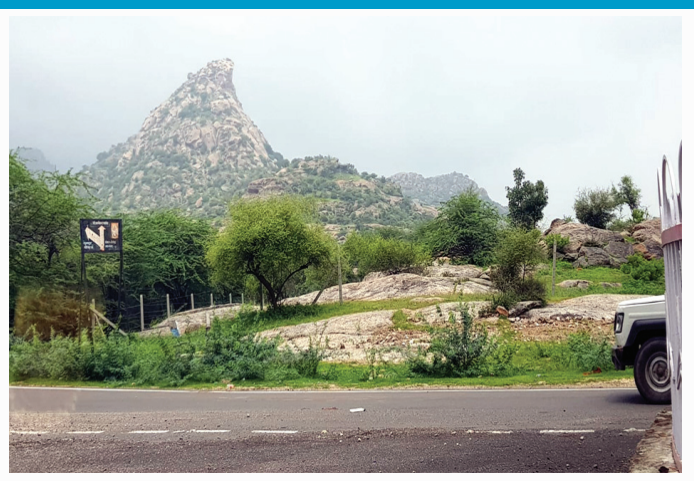

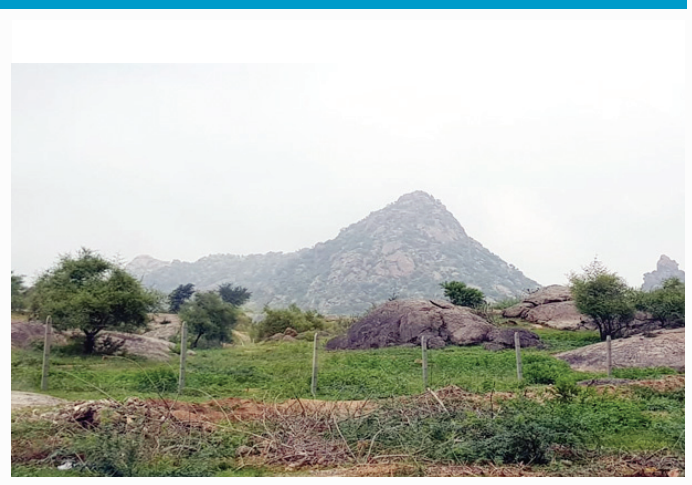

शिवगंज उपखंड क्षेत्र के जवाई कन्वर्जन एरिया के अंदर लोगों ने फॉरेस्ट की लैंड को भी नहीं छोड़ा गोचर को तो छोड़ ही नहीं रहे क्योंकि प्रशासन गोचर भूमि पर कब्जा करवाने की गारंटी दे रहा है कितने बड़े निर्माण हो रहा है अगर प्रशासनिक अधिकारियों सेक्रेटरी पटवारी सहित उस पंचायत के सभी अधिकारियों का पता होने के बाद भी उस पहाडियों पर अवैध निर्माण को नहीं रुकवा रहे है तो समझ जाओ कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा फॉरेस्ट जमीन जो जंगली जानवरों के लिए आरक्षित होती है उस पर भी लोगों ने बड़ी-बड़ी होटल आलीशान रिसोर्ट टेंट नुमाए होटल का निर्माण हो रहा है क्या प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं जाते या पटवारी वह उस पंचायत के कर्मचारियों का ध्यान उस तरफ नहीं जाता है अधिकारी ऑफिस में वह टेंडर में कोटेशन बिलों पर पूरी नजर रहती है ना की तो सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का ध्यान नहीं रखेंगे यह लोग अगर इनका सह नहीं हो तब तक निर्माण एक इंच भी नहीं हो सकता उनके आशीर्वाद वह शहर से ही अवैध निर्माण अतिक्रमण हो रहे हैं गोचर भूमि गौ माता के लिए आरक्षित होती है वहां पर गौशाला गौमाता के खाने की व्यवस्था होनी चाहिए पर उस पर लोगों के मकान बन रहे हैं लोग आलीशान रिसोर्ट बना रहे कोई भूमाफियाओ ने तो जमीनों को आगे से आगे बेच रहे अपना घर चलाने के लिए गौमाता की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं वह उसको आगे से आगे बेच रहे क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का आशीर्वाद उनके बताइए उनको पता होने के बाद भी गोचर भूमि की रजिस्ट्री कैसे होती है क्या रजिस्टार विभाग रजिस्ट्री करने से पहले इनको पता नहीं होता कि वह जमीन किस किस्म में है मोटेशन भरते वक्त भी उसका ध्यान रखें तो वह भी वह जमीन उसके नाम की नहीं हो सकती पर धन के आगे सब नतमस्तक्त है क्योंकि भ्रष्टाचार की शर्म सीमा पार कर चुके है अगर ऐसे नरेंद्र मोदीजी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अकेले क्या करेंगे उस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म करेंगे यहां पर बैठे नेताजी विधायक लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अधिकारियों पर लगाम लगानी होगी नहीं तो यह अधिकारी ही इन नेताओं को आगे से आगे बेच देते हैं इन नेताओं को पता ही नहीं होता कि यह जमीन किस्म है और वह उनको कौन समझाए अधिकारी व कर्मचारी तो सरकार के नौकर है वहाँ पर लोग ही इनको अवैध काम करवाएंगे अतिक्रमणियों का सपोर्ट करेंगे वह गोचर फॉरेस्ट की जमीन का सेटलमेंट कर उनके नाम के लिए दबाव बनाकर ऐलॉटमेंट भूमाफियाओ के नाम की नहीं करवाएंगे तो वह जमीन इन पशुओं की वह जंगली जानवरों के लिए आरक्षित रह जाएगी नहीं तो यह भूमाफियाओ ने अपने नाम की ऐलॉटमेंट करवा कर आगे से आगे बेच देंगे ऐसे भी इन भूमाफियाओ के नाम की करोड़ों रुपए की जमीन आज भी पड़ी है फिर भी यह गोचर की भूमि वह फॉरेस्ट की जमीन को नहीं छोड़ रहे क्योंकि नेताओं को पैसा देकर आप कुछ भी कर सकते हो ऐसा कब रोका जाएगा इन भूमपियाओं को वह ऐसे अधिकारियों को जो भूमाफियाओं का साथ देकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाएंगे प्रशासनिक अधिकारी अभी इन अवैध कार्य का साथ देंगे या यह फॉरेस्ट की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण गोचर भूमि पर बना रही बड़ी-बड़ी होटल पर से अतिक्रमण कब हटाया जाएगा या बड़े अधिकारी ही यह कार्य करवा रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि इस पहाड़ियों के पास में जवाई बांध की पहाड़ियां आती है वहां पर तेंदूए टाईगर भालू नीलगाय हिरण सहित सैकड़ो जानवर इन जंगलों में पाए जाते हैं यह अधिकारी इन होटल मालिकों से बड़ी वसूली कर इन होटल मालिक को जानवर बताने का ठेका दिया जा रहा है इसलिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ही अतिक्रमण नहीं हटाने की कार्रवाई से निलंबित करना चाहिए तभी जंगली जानवर सुरक्षित रह सकते हैं अन्यथा नहीं क्योंकि यह लोग ही उनका सपोर्ट करते हैं जिससे जंगली जानवर प्रभावित होते हैं इनका क्या कहना है शिवगंज पंचायत के उपखंड क्षेत्र में आने वाले सभी गांव पंचायत में हजारों बिधा जमीन गोचर के नाम की पड़ी है उस पर सैकड़ो बिधा जमीन पर शहर के माने हुए भूमाफियाओ ने कब्जा कर लिया वहां पर बड़ी-बड़ी होटल रिसोर्ट आलीशान टेंट नुमा होटल हो रही है यह सभी जंगली जानवरों के शिकार का करवाने का लोगों को आकर्षित करते हैं जंगली जानवरों का शिकार करते हैं फिर भी फॉरेस्ट अधिकारी चुप क्यों बैठे क्यों नहीं रुकते अपने एरिया में जंगली जानवरों के शिकार के बारे में पर यहां पर कुछ नेताओं ने अधिकारियों पर दबाव देकर इन फॉरेस्ट गोचर की भूमि का ऐलोटमेंट करने का आदेश दिया था वह दबाव डालने की कोशिश की गई शहर के धन्ना सैठो ने भूमाफियाओ के नाम की सैकड़ो बिधा जमीन आज भी अतिक्रमण हो रहा है बड़ी-बड़ी होटले हो रही है यहां पर जंगली जानवर रहते हैं वहां पर ही बड़ी माईनिंग ब्लास्ट करना जंगली जानवरों का शिकार करना क्या हो रहा है यह क्षेत्र ही इन जंगली जानवरों के लिए आरक्षित किया हुआ है फिर भी इन पहाड़ियों में ब्लास्टिंग होना बड़े-बड़े पत्थरो को निकालना वह पहाड़ियों पर होटल बनाना कितना सही होगा या यह अधिकारी इन माईनिंग वह फौरेसट गोचर भूमि पर से अतिक्रमण हटाएंगे या यह कब्जे ऐसे कैसे ही चलेंगे वह जंगली जानवरों के जीवन पर खतरे की घंटी हमेशा बस्ती रहेगी देखते हैं कब करवाई होती है

सीमादेवी माली पाषॅद नगर पालिका शिवगंज

जवाई रिजर्वेशन एरिया के अलावा अन्य पहाड़ियों पर वह आसपास पडी सरकारी जमीनों जैसे गोचर की भूमि फौरेसट की जमीन पर यह अधिकारी मिलकर कब्जा करवा रहे क्यों नहीं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी तभी यह कभी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करवाएंगे क्योंकि तुरंत ही यह अतिक्रमण मुक्त करवा कर सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया जाए जितने भी सरकारी जमीन पर होटल रिसोर्ट टेंट नुमा होटल बनी उन सभी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए जंगली जानवरों की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए जंगली जानवरों का प्रवचन बढ़ सके और सैकड़ो की ताकत में जंगली जानवरों की रक्षा करें कामबेश्वर महादेव की पहाड़ियां बेड़ा के आसपास वह इन पहाड़ियों के आस पास जितने भी अवैध होटले बनी तुरंत हटाई जाए तब जाकर जंगली जानवरों का शिकार नहीं हो सकेगा यह होटल की आड़ में जंगली जानवरों का शिकार भी करवा रहे है। **जैसाराम माली अध्यक्ष जवाई पर्यावरण एवं वन विकास समिति शिवगंज**

वाहन चोरी का खुलासा,एक आरोपी गिरफ्तार

द पुलिस पोस्ट

बिजयनगर ब्यावर सीपी तिवाड़ी। बिजयनगर पुलिस ने वाहन चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से बरामद की मोटरसाइकिलें।जानकारी के अनुसार प्रार्थी उम्मेद सिहं ने थाने मे रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वो बिजयनगर एसबीआई बैंक मे काम से आया था। उसकी मोटरसाईकिल आरजे 01 क्यूएस 7198 वाहन मॉडल बजाज प्लेटिना 100 सीबीएस बैंक के बाहर खडी कर बैंक के अन्दर चला गया। वो जब वापस बैंक से बाहर आकर देखा तो उसकी मोटरसाईकिल नही दिखी तो उसने बैंक के आस पास काफी तलाश की पर उसे नही मिली। जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोर व मोटर साईकिल की तलाश शुरू की। माल मुल्जिमान की तलाश बाबत टीम गठित की जाकर सम्भावित स्थान पर दबिश दी गई व मुखबिरान खास मामूर किये गये। मुखबीर खास ने बताया की बैंक के बहार से जो मोटरसाईकिल चोरी हुई वो मोटरसाईकिल आसन बड़ा के धर्मीचन्द गुर्जर के पास है सूचना विश्वसनीय होने से मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति को डिटेन कर पुछताछ की गई तो मोटरसाईकिल चोरी करना स्वीकार किया। जिस पर थाना अधिकारी राजमल कुमावत के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की । पुलिस टीम में राजमल कुमावत थाना इंचार्ज शेर सिंह हेड कॉन्सटेबल नरेंद्र कुमार प्रीतम सैनी वीरेन्द्र बलवीर।

21 अगस्त के प्रस्तावित भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए सजगता और समन्वय से कार्य करें-जिला कलक्टर मेहता

जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लेकर दिए दिशा-निर्देश

द पुलिस पोस्ट

भीलवाड़ा, 19 अगस्त। गत दिनों माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी/एसटी आरक्षण के सम्बंध में दिए गये निर्णय के सम्बंध में कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आव्हान कर आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आव्हान किया है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने इस बंद के दौरान जिले में कानून व्यवस्था, शांति व यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था की सोमवार को आयोजित बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहाँ पहुंचेगा आदि जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से साझा करें। व्यापार मंडल, शांति समितियों के प्रतिनिधियों से निरन्तर बातचीत करें। महापुरूषों की मूर्तियों, रेल व बस स्टेशनों के पास पर्याप्त जाब्ता रखे। क्षेत्र में कोई मेला, उत्सव आयोजित हो रहा है तो वहाँ भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती रखें। वीसी के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलीजेंस के माध्यम से पल-पल सूचना जुटाकर सम्बंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भडकाने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन रतन कुमार सहित सभी उपखंड अधिकारी और पुलिस के अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

शार्ट न्यूज

राष्ट्रपति से मिलने दिल्ली पहुंचे पं. बंगाल के राज्यपाल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल बोस गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का पतन हो रहा है। मौजूदा सरकार ने महिलाओं को निराश किया है। ऐसा नहीं चलेगा और उनके सामने सभी सांविधानिक विकल्प खुले हैं।

माकपा नेता सीताराम येचुरी एम्स में भर्ती

नई दिल्ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी को तेज बुखार की शिकायत के बाद सोमवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, येचुरी को शाम को अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया। माकपा के एक सूत्र ने बताया कि वह जांच के लिए गए थे और निमोनिया के कारण उन्हें भर्ती कराया गया। उनका उपचार जारी है और फिलहाल वह ठीक हैं। माकपा नेता का हाल ही में मोतियाबिंद का आपरेशन हुआ था।

अनूसूचित जाति-अनूसूचित जनजाति के आरक्षण

आज भारत बंद, प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित

भारत बंद के चलते जारी किए गए आदेश में यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा, बाकि अन्य स्टाफ तय समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे

जयपुर।

बुधवार यानी 21 अगस्त को अनूसूचित जाति-अनूसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद को देखते हुए राजस्थान के कई जिलों में 12वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान सभी कोचिंग संस्थान व स्कूल आज, 21 अगस्त को बंद रहेंगे।

12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित

जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित करते हुए कहा कि बंद के दौरान जयपुर में रैली, प्रदर्शन व जाम की स्थिति रह सकती है। ऐसे में स्कूली बच्चे वाहनों में फंसे रह सकते हैं। इसलिए कक्षा 1 से 12वीं तक के सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाता है। स्कूल के अलावा जिले में सभी कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे।

कई राजनीतिक दलों ने बंद का किया समर्थन

राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी ने भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन सड़कों पर उतरने से दूरी बनाई है। पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हमारा भारत बंद को समर्थन है, लेकिन सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन, शहर बंद जैसा कोई काम नहीं करना है। इसके अलावा बसपा ने भी बंद का समर्थन किया है। प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार पार्टी शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगी।

केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा अवकाश

जयपुर के अलावा दौसा, बाड़मेर और डीग समेत कई जिलों में भी 12वीं तक के सरकारी व प्राइवेट स्कूल में 21 अगस्त को छुट्टी रहेगी। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों व सभी कोचिंग संस्थान व लाइब्रेरी में भी अवकाश घोषित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगा, बाकि अन्य स्टाफ तय समय पर विद्यालय में उपस्थित रहेंगे।

क्या हैं दो शर्त

एससी के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकतीं।
एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था, जिनमें कहा गया था कि एससी और एसटी के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं।

झुंझुनूं में घर घर जाएगी पशुपालन विभाग की टीम

6 लाख पशुओं को लगाई जाएगी वैक्सीन, 26 अगस्त से शुरू होगा अभियान

एजेंसी

झुंझुनूं। पशुपालन विभाग की ओर से पशुओं को खुरपका व मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए 26 अगस्त से अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाकर टीकाकरण करेगी। अभियान 25 अक्टूबर तक चलेगा। झुंझुनूं पशुपालन विभाग के उपनिदेशक सुरेश ने बताया कि झुंझुनूं में 6 लाख 16 हजार 206 पशुओं के टीकाकरण किया जाएगा। 5 लाख 13 हजार 400 वैक्सीन आ चुकी है। टीम घर घर जाकर टीकाकरण करेगी। पशुपालकों से टीकाकरण का कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। अभियान दो माह तक चलेगा।

टैग भी लगाया जाएगा

टीकाकरण के साथ पशुओं के टैग लगाने का काम भी होगा। केन्द्र सरकार ने पशुओं का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करने के लिए टैग लगाने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पशुओं की नस्लों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है। इस योजना में पशुओं की पहचान के लिए उनके कान पर एक पीले रंग का टैग लगाया जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पंजीकृत पशुओं को ही प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। टैग लगे पशुओं के लिए दवाओं की भी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस योजना में फसल बीमा की तरह पशुओं का भी बीमा होता है। लेकिन बीमा के लिए टैगिंग अनिवार्य है। टैग लगे पशुओं की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी ऑनलाइन रहेगी। टैग लगने से खोए या चोरी हुए पशुओं का भी पता लगाना आसान हो जाएगा। इससे पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री भी आसानी से संभव हो जाएगी।

साल में दो बार लगते हैं टीके

गाय व भैंस में प्रमुख रूप से होने वाली खुरपका - मुंहपका बीमारी के जानलेवा होने व इसके एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैलने के कारण पशुपालन विभाग प्रदेश में इस बीमारी का पूरी तरह उन्मूलन करने के लिए प्रयासरत है। इस बीमारी से बचाव के लिए साल में दो बार टीकाकरण किया जाता है।

सीआरपीएफ जवानों पर आतंकी हमला, एक निरीक्षक शहीद

जम्मू ▪ एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में सोमवार को गश्ती दल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक निरीक्षक शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बसंतगढ़ में डुडू थानाक्षेत्र के चिल इलाके में अपराह्न करीब साढ़े तीन बजे आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) पर गोलीबारी की।

उन्होंने बताया कि हमले में सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन के निरीक्षक कुलदीप को गोली लगी और बाद में अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। उधमपुर पुलिस ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''चिल, डुडू में गश्त के दौरान आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों पर

गोलीबारी की। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक निरीक्षक को गोली लगी और वह शहीद हो गए। अभियान जारी है। अधिकारियों ने कहा कि संयुक्त गश्ती दल की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकवादी मौके से भाग गए। घटनास्थल पर अतिरिक्त बल भेजा गया है तथा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग द्वारा जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा किए जाने के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां 'हाई अलर्ट' पर हैं।

भक्तों को दर्शन देने निकले भगवान महाकाल

श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भगवान महाकालेश्वर की सवारी धूमधाम से निकाली गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इसमें शामिल हुए।

सिद्धारमैया को राहत, मुडा मामले में 29 तक कार्रवाई पर रोक

बेंगलुरु ▪ एजेंसी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी/एमएलए कोर्ट को निर्देश दिया कि वह कथित मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) स्थल आवंटन घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ 29 अगस्त तक कोई कार्यवाही न करे। इसी दिन सीएम के खिलाफ शिकायतों के मामले की सुनवाई होनी है। सीएम सिद्धारमैया की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मैंने प्रथमदृष्टया प्रस्तुतीकरण पर विचार किया। यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही इस बात पर आदेश के लिए लंबित है कि मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं।

मुख्यमंत्री के खिलाफ आगे की कार्रवाई की अनुमति देने वाला कोई भी आदेश इस अदालत के समक्ष कार्यवाही को विफल कर देगा। चूंकि कार्यवाही इस अदालत के समक्ष लंबित है और दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसलिए मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित अदालत अपनी कार्यवाही स्थगित रखेगी। इन शिकायतों के संबंध में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता राज्यपाल थावरचंद गहलोत की ओर से पेश हुए।

घुसपैठ करते 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार

अगरतला ▪ एजेंसी

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हालातों पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच, भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ हो रही है। त्रिपुरा में पुलिस ने तीन स्थानों से 18 बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी मदद कर रहे पांच भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सहायक महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अनंत दास ने कहा, 'पुलिस को सूचना मिली थी कि त्रिपुरा के गुमती जिले के लामप्रपारा में बांग्लादेशी नागरिकों का एक दल मौजूद है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू की और आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। शनिवार को बांग्लादेश के सात नागरिकों और उनकी मदद करने वाले पांच भारतीय नागरिकों को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के सिधई क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। एक अभियान के दौरान पश्चिम त्रिपुरा के एमबीबी हवाई अड्डा क्षेत्र से सोमवार को तीन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा सीमा पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

मंकीपॉक्स को लेकर भारत में एयरपोर्ट-सीमा पर अलर्ट

नई दिल्ली ▪ एजेंसी

खतरनाक एमपॉक्स यानी मंकीपॉक्स ने अब भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में दस्तक दे दी है। ऐसे में इसने भारत के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। इसके मद्देनजर केंद्र ने बांग्लादेश और पाकिस्तान हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सीमाओं पर अधिकारियों को आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। साथ ही सरकार ने अस्पतालों को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करने को कहा गया है। एमपॉक्स रोगियों का अलग से इलाज करने के लिए दिल्ली में तीन सरकारी अस्पतालों को प्रमुख सुविधाओं के रूप में चुना गया है। इन तीन अस्पतालों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल के नाम शामिल हैं।

संक्रामक और जहरीला वायरस

इस बार का वायरस स्ट्रेन अलग है और अधिक जहरीला और संक्रामक है। लेकिन मौजूदा आकलन के अनुसार, देश में निरंतर प्रसारण के साथ बड़े प्रकोप का जोखिम कम है।2022 के बाद से भारत में कम से कम 30 एमपॉक्स के मामले सामने आए हैं। एमपॉक्स का आखिरी मामला इसी साल मार्च में सामने आया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने एमपॉक्स को अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है।

कोलकाता कांड : सीबीआई को अदालत से मिली इजाजत

आरोपी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, उगलेगा सच्चाई

कोलकाता ▪ एजेंसी

कोलकाता रेप-मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय कापॉलीग्राफी टेस्ट कराने की सीबीआई को इजाजत मिल गई है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इससे पहले एजेंसी आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चल सकेगा कि आखिरी आरोपी कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है। संजय रॉय, इस केस में मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इससे पहले आरोपी के मनोवैज्ञानिक टेस्ट में यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आरोपी

मेंटली ठीक है या नहीं। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से यह भी पता चल सकेगाकि आरोपी ने घटना को अकेले अंजाम दिया, या फिर आरोपी जो भी दावा कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है।

संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट संभव

कोलकाता रेप केस में आरजी कर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में हैं। सीबीआई ने घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की है। संदीप घोष के बयान में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। सीबीआई की टीम ने पीड़िता के घर जाकर उसके माता-पिता से पूछताछ की है। डॉक्टर के पिता ने खुलासा किया कि उनकी बेटी एक निजी डायरी अपने बैग में रखती थी, जिसमें वह अपनी जिंदगी से जुड़े विचार लिखती थी। उन्होंने सीबीआई से इस डायरी की सामग्री पर सार्वजनिक रूप से चर्चा न करने का अनुरोध किया है। पीड़िता की मां ने कहा, "ममता बनर्जी की सभी योजनाएं - कन्याश्री योजना, लक्ष्मी योजना - सभी छद्म हैं। जो कोई भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है, उनका लाभ उठाने से पहले कृपया यह देख लें कि क्या आपके घर की लक्ष्मी सुरक्षित है।

राज्यपाल से मिली महिलाएं

ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस से सोमवार को एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान महिलाओं और ट्रांसजेंडरों ने घटना पर दुख जताया। साथ ही प्रशासनिक और कानून प्रवर्तन की गड़बड़ियों पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। राज्यपाल के सामने उन्होंने महिलाओं, विशेष रूप से चिकित्सा पेशेवरों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जांच को सही दिशा में ले जाने पर जोर दिया। प्रतिनिधियों ने राज्य और देश भर में चिकित्सा पेशेवरों और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की।

तैरह हजार अमरनाथ यात्रियों की रेस्क्यू टीमों ने बचाई जान

जम्मू ▪ एजेंसी

अमरनाथ यात्रा सोमवार को समाप्त हो गई है। यात्रा के दौरान माउंटेन रेस्क्यू टीमों ने 13 हजार श्रद्धालुओं की जान बचाई। एक दर्जन से अधिक माउंटेन रेस्क्यू टीमों ने श्री बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की मदद की। बीस हजार से अधिक श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई तो बीमार हुए कई श्रद्धालुओं को नजदीकी कैंपों तक पहुंचाया।

माउंटेन रेस्क्यू टीमों में जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल थे। इन टीमों को श्री बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही 24 जून को यात्रा के दोनों मार्गों पर संवेदनशील जगहों पर तैनात कर दिया गया था। पहलगाम यात्रा मार्ग पर 8 माउंटेन रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया था जबकि बालटाल रोड पर पांच टीमें तैनात रही।

विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण लागू करने, संघ में मंथन

नई दिल्ली । 31 अगस्त से 2 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक आयोजित हैं। इस बैठक में राज्यसभा और विधान परिषदों में आरक्षण लागू हो। इस पर अंतिम फैसला हो सकता है। दिल्ली में हुई संघ के पदाधिकारी की बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई है। जाति जनगणना और आरक्षण के मामले में जिस तरह की राजनीति, राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है। उससे निपटने के लिए यह प्रस्ताव रामबाण माना जा रहा है। राजनेता राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण लागू किया जाता है, तो वह जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर जिस तरह की सक्रियता बरत रहे हैं। यदि उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो वह शांत हो जाएंगे। संघ को लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने जैसे विषयों से संघ की छवि में बुरा असर पड़ा है। उस छवि को सुधारने के लिए,राज्यसभा और विधान परिषद मेंआरक्षण देने की मांग संघ करेगा। जिस तरह का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लागू है। वही आरक्षण संख्या के आधार पर विधान परिषद और राज्यसभा में दिया जाए।

बेंगलुरू : यौन उत्पीड़न पीड़िता के खिलाफ हिट एंड रन का केस

बेंगलुरू । नागालैंड की एक स्नातक छात्रा के साथ बेंगलुरु में हुए यौन उत्पीड़न के मामले में नया मोड़ आ गया है। यातायात पुलिस ने छात्रा पर शराब पीकर वाहन चलाने और कई दुर्घटनाएं करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, बीसीए स्नातक की छात्रा 17 अगस्त को कोरमंगला इलाके में एक पब में पार्टी में शामिल होने के बाद नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी। नशे में ठीक से गाड़ी नहीं चला पाने के कारण उसकी कार दो ऑटो-रिक्शा और एक बाइक से टकराई। वाहनों से टकराने के बाद भी वह मौके पर नहीं रूकी और वहां से भाग गई। इस घटना में जिन ऑटो चालकों के वाहन क्षतिग्रस्त हुए उन्होंने छात्रा का पीछा कर छात्रा को पकड़ लिया। इसके बाद पीड़िता ने ऑटो चालकों के साथ तीखी बहस की। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब उसके पुरुष मित्र ने छात्रा को परेशानी से बचाने के लिए दूर भेज दिया। महिला बाइक पर सवार होकर भागने में कामयाब रही। इस बीच, पीड़िता बाइक से उतरकर दूसरे दोपहिया वाहन पर सवार हो गई। आरोपी स्कूटर सवार मुखेश्वरन उर्फ मुकेश (24) जो बेंगलुरु के ओदूगोडी का ही रहने वाला है, पीड़िता को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। बता दें कि फिलहाल पीड़िता का अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़िता ने अपने बचाव की काफी कोशिश की, जिससे आरोपी के चेहरे पर खरोंच आई। पीड़िता ने अपने दोस्त को इमरजेंसी मैसेज भेजकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद छात्रा की लोकेशन का पता लगाया गया। पीड़िता एक ट्रक के पीछे नग्न अवस्था में मिली थी। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई है कि पीड़िता नशे की हालत में थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए पांच टीमें बनाई हैं। इस बीच यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रही पुलिस ने संदिग्ध द्वारा युवती को अपराध स्थल तक ले जाने के स्थान से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में लगे 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। 40 अधिकारियों की एक टीम ने दोनों स्थानों पर सक्रिय 1,000 फोन नंबर एकत्र किए।

स्कूल में छात्राओं के यौन शोषण के बाद बदलापुर में उग्र प्रदर्शन, पटरी पर उतरे लोग

बदलापुर । महाराष्ट्र के बदलापुर में एक स्कूल में दो छात्राओं के साथ यौन शोषण के बाद शहर में आक्रोश फैल गया। घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर जगह-जगह प्रदर्शन किए, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मुंबई से सटे ठाणे में दो छात्राओं के यौन शोषण का मामला सामने आया है। इन छात्राओं के परिजनों सहित अन्य सैकड़ों लोगों ने स्कूल का गेट बंद कर हंगामा किया। इसके बाद परिजन रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां पहले रेल की पटरी पर बैठकर प्रदर्शन किया, फिर जमकर तोड़फोड़ करते हुए पथराव किया। इसकारण तीन घंटे तक इस रूट पर लोकल ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ। हालांकि पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों से शांत रहने की अपील की है। उधर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। इसके बाद वरिष्ठ आईपीएस आरती सिंह के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। चूंकि अब तक स्कूल प्रबंधन चुप्पी साध रखी हैं, इसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मामले में जल्द से जल्द अदालती कार्रवाई पूरी कराने के लिए केस को फास्ट ट्रैक में भेजा जाएगा। इस घटना के चार दिन बाद भी न्याय नहीं मिलता देख सैकड़ों की संख्या में लोग मंगलवार की सुबह स्कूल पहुंचे और गेट बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया।

नकली शराब पीने से 17 लोगों की तबीयत बिगड़ी, पांच गंभीर

गंजम। ओडिशा के गंजम जिले में नकली देशी शराब पीने से कम से कम 17 लोगों की तबीयत खराब हो गई जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गंजम जिले के कर्बलूआ गांव के करीब 20 लोगों ने सोमवार को माउंडपुर गांव में देशी शराब पी थी, जिसके बाद उनमें से 17 लोगों को बेचैनी और उल्टी होने लगी। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां जहां पांचों लोगों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें ब्रह्मपुर शहर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेफर किया गया। चिकिटी विधायक मनोरंजन दयान सामंत्रा मौके पर पहुंचे और आरोप लगाया कि आबकारी विभाग अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए नियमित छापेमारी नहीं कर रहा है।

अटारी बार्डर पर जवानों की नहीं रही कलाई सुनी, बहनों का प्यार देख जवान हुए भावुक

अमृतसर। अपने घरों से दूर सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भी रक्षाबंधन मनाया। रक्षाबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय अटारी सीमा पर बहनों ने इन जवान भाइयों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधा और देश की रक्षा का संकल्प लिया। सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान बहनों का प्यार देखकर भावुक हो गए। 1968 से अटारी सीमा पर जवानों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधने का यह क्रम आज भी जारी है। रक्षाबंधन पर प्रो. चावला महिलाओं के साथ अटारी सीमा पर पहुंचीं तो जवानों ने उनका स्वागत किया। प्रो. चावला ने बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट गौरव शर्मा की कलाई पर राखी बांधी और देश की रक्षा का संकल्प लिया। इसके बाद कई स्कूलों

की छात्राओं ने जवानों को राखी बांधी। प्रो. चावला ने कहा हमारे जवान अपने घरों से सैकड़ों मील दूर सीमाओं पर युद्ध और शांतिकाल में देश की सेवा करते हैं तो उनकी कलाई राखी के दिन सूनी नहीं रहना चाहिए। इसी भावना से 1968 में अटारी सीमा पर बीएसएफ के जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। प्रो. चावला ने बताया कि 56 सालों से यह काम कर रही हैं। पंजाब में आतंकवाद के दौर 1992 में जब अमृतसर के गली-बाजारों में सुरक्षा बलों के जवान विशेषकर सीआरपीएफ ही दिखाई देती थी ऐसे में रक्षाबंधन पर जगह-जगह डेरा डालकर बैठे जवानों को वहीं राखी बांधी गई थी। पंजाब के तत्कालिक डीजीपी स्व. केपीएस गिल की कलाई पर 1992 में राखी बांधी थी, तब गिल ने मुझसे वायदा किया था कि बहनजी अगले साल जब राखी बंधवाने आऊंगा, तब पंजाब से आतंकवाद का सफाया हो चुका होगा। 1993 में आतंकवाद के सफाए के बाद स्व. गिल ने अपना यह वायदा निभा दिया। प्रो. चावला ने कहा कि मैं इस दिन की बेसब्री से प्रतीक्षा करती हूं। इन जवानों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपतत्व का अहसास करवाया जाता है। इस अवसर पर बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट गौरव शर्मा ने कहा कि राखी से हमें व हमारे सैनिकों को ताकत मिलती है। रक्षाबंधन का पर्व सभी में राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करता है। हमारे जवान सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमारे हाथों में देश सुरक्षित है।

मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा और रघुराम राजन समेत कई लोगों की लेटरल एंट्री हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कांग्रेस पर वरिष्ठ नौकरशाही में लेटरल एंट्री की सरकार की पहल पर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कदम से अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती प्रभावित नहीं होगी। वैष्णव ने कहा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री 1970 के दशक से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों के दौरान होती रही है। लेटरल एंट्री वाले नौकरशाहों का कार्यकाल तीन साल का है जिसमें दो साल का संभावित विस्तार शामिल है। वैष्णव ने कहा कि मनमोहन सिंह ने 1971 में तत्कालीन विदेश व्यापार मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में लेटरल एंट्री से प्रवेश किया था और वित्त मंत्री बने और बाद में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि इस रास्ते से सरकार में शामिल हुए अन्य लोगों में सैम पित्रोदा और वी कृष्णमूर्ति, अर्थशास्त्री बिमल जालान, कौशिक बसु, अरविंद विरमानी, रघुराम राजन और अहलूवालिया हैं। जालान सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। विरमानी और बसु को भी क्रमशः 2007 और 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने पूर्व

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया

अतीत में की गई ऐसी पहल के प्रमुख उदाहरण हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि प्रशासनिक सेवाओं में लेटरल एंट्री के लिए प्रस्तावित 45 पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की कैडर संख्या का 0.5 प्रतिशत हैं, जिसमें 4,500 से अधिक अधिकारी शामिल हैं और इससे किसी भी सेवा की सूची में कटौती नहीं होगी।राजन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में भी काम किया और बाद में 2013 से 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। अहलूवालिया को शैक्षणिक और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से सरकारी भूमिकाओं में लाया गया था। उन्होंने 2004 से 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वैष्णव ने कहा कि इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि को 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया था।

लेटरल एंट्री पर सरकार ने पीछे किए कदम.. विज्ञापन वापस लेने को कहा

नई दिल्ली । लेटरल एंट्री को लेकर मचे सियासी बवाल पर मोदी सरकार की ओर से कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है। मंत्री सिंह ने पत्र में संघ लोक सेवा आयोग से लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों को वापस लेने को कह दिया है। पत्र में कहा गया है कि लेटरल एंट्री के आधार पर निकाली गई भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान में रखकर वापस लिया जाए। पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च पदों पर लेटरल एंट्री के लिए संविधान में निहित सामाजिक न्याय और आरक्षण पर जोर देना चाहते हैं। इसकारण इस विज्ञापन को वापस लिया जाय। केंद्र ने पत्र में सामाजिक न्याय के प्रति संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। केंद्र ने कहा कि हाशिए पर मौजूद योग्य उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी जरूरत है। उल्लेखनीय है कि 17 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग ने लेटरल एंट्री के आधार पर नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किए थे जिसका कांग्रेस सहित विपक्ष ने विरोध किया था। विपक्ष का कहना है कि इससे आरक्षण खत्म होगा और सामाजिक न्याय की बात अधूरी रहेगी। बीते दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार लेटरल एंट्री के जरिए दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग से उनका आरक्षण छीनने की कोशिश कर रही है, जो कि स्वीकार्य नहीं है।

देश का मुसलमान शरिया कानून से नहीं करेगा समझौता

-पीएम मोदी के 15 अगस्त पर यूसीसी के बयान पर भड़के संगठन

नई दिल्ली (एजेंसी)। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का जिक्र पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से किया था। अब उसको लेकर मुस्लिमों ने बड़ा ऐलान किया है। देश का मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने यूसीसी पर देश की आजादी के दिन बड़ा बयान दिया तो इसके कुछ न कुछ मायने तो जरूर ही होंगे। पीएम मोदी के बयान के बाद मुस्लिम संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम मोदी के सेक्युलर सिविल कोड पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बोर्ड का कहना है कि मुसलमान शरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे, इसलिए समान या सेक्युलर नागरिक संहिता स्वीकार नहीं की जाएगी।

पीएम मोदी ने देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता (एससीसी) की जोरदार वकालत करते हुए भारत को 'विकसित राष्ट्र' बनाने का संकल्प और 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का सपना साकार करने का आह्वान किया था। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं, वह सचमुच में साम्प्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार रखें। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऊंच-नीच का कारण बन जाते हैं। उन कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। देश की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो।

बता दें कि भारत के संविधान का आर्टिकल 44 कहता है कि राज्यों को अपने नागरिकों के लिए सामान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। संविधान निर्माताओं ने अपने दौर में इसे लागू नहीं किया और भविष्य में इसका फैसला संसद पर छोड़ दिया था। जिससे सहमति के बाद इसे बनाया जा सके लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हो पाया है। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो मुसलमान इसका विरोध करते हैं।

झारखंड में चंपई सोरेन की बगावत के बाद बिहार में बढ़ी हलचल, नीतीश के मंत्री ने किए चौंकाने वाले दावे

पटना (एजेंसी)। झारखंड की राजनीति में पल पल बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम का प्रभाव बिहार में भी पड़ने की संभावना दिखने लगी जब नीतीश कुमार के करीबी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ झारखंड में महागठबंधन की सरकार के साथ हो रहा है, उनके विधायक विद्रोह कर बीजेपी का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही बिहार में भी महागठबंधन के विधायकों के साथ बहुत जल्द होने वाला है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली में जमे हुए हैं। जानकारी के अनुसार वे बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। वहीं, जेएमएम वेट एंड वाच की स्थिति में है और जेएमएम को चंपई सोरेन के अगले कदम का इंतजार है। लेकिन, इसका असर न सिर्फ जेएमएम पर पड़ेगा, बल्कि इसका प्रभाव झारखंड की महागठबंधन की सरकार पर भी पड़ सकता है। बल्कि, दिलचस्प ये कि अब झारखंड की राजनीतिक उठापटक की आंच बिहार की सियासत पर भी पड़ने की संभावना बढ़ गई है। कम से कम नीतीश कुमार के एक करीबी मंत्री के दावे से यही बात निकलकर आ रही है।

अशोक चौधरी दावा करते हुए कहते हैं कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक एनडीए के संपर्क में हैं और बहुत जल्द वैसे विधायक हमारे साथ होंगे। अशोक चौधरी कहते हैं कि आज झारखंड में जो कुछ हो रहा है तब इन लोगों

की बेचैनी बढ़ रही है और आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब कुछ महीना पहले महागठबंधन के लोग हमारे विधायकों को तोड़कर सरकार गिराने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए तब क्यों नहीं जुबान खुली थी। अशोक चौधरी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस विधायकों की नाराजगी की वजह भी बताते हैं जिसके कारण वो एनडीए के संपर्क में आए। कई विधायकों को आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व ने बड़े बड़े सपने दिखाए, टिकट देने का वादा किया लेकिन कुछ किया नहीं वैसे विधायकों की नाराजगी अब खुलकर सामने आएगी और बहुत जल्द ऐसे विधायक हमारे साथ होंगे। अशोक चौधरी के दावे पर सियासत गर्म हो गई साथ ही पलटवार भी महागठबंधन की तरफ से शुरू हो गया। आरजेडी की प्रवक्ता एजया यादव कहती है जदयू के नेता खुशफहमी में हैं और उनका दावा भी हवा में उड़ जाएगा।

भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, हरियाणा से किरण चौधरी को टिकट

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। वहीं राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू भी मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली किरण चौधरी भी हरियाणा से राज्यसभा की उम्मीदवार होगी। राज्यसभा चुनाव 3 सितंबर को होने हैं।

भाजपा के उम्मीदवारों की बात करें तो असम से मिशन रंजन दास और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार से मनन कुमार मिश्रा पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिहार के एक और सीट से भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को टिकट दिया गया है

जबकि उड़ीसा से ममता मोहंता भाजपा की उम्मीदवार होंगी। त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्यजी भाजपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचेंगे।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि नौ राज्यों की 12 रिक्त राज्यसभा सीट के लिए तीन सितंबर को चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्रियों-पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की दस सीट खाली हो गई थीं। तेलंगाना और ओडिशा में राज्यसभा की दो सीट के लिए उपचुनाव भी होगा। तेलंगाना में हाल में के. केशव राव ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था जबकि बीजू जनता दल (बीजद) की सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए 'रात के साथी' प्रोग्राम ममता ने किया शुरू, गाइडलाइन को लेकर क्यों छिड़ गया विवाद

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले के मद्देनजर पश्चिम बंगाल सरकार ने अस्पतालों में महिला कर्मियों की सुरक्षा के लिए 17 सूत्री दिशानिर्देश जारी किए हैं। हालांकि, महिलाओं के लिए रात की पाली को कम करने के दिशानिर्देशों में से एक की तीखी आलोचना हुई है।

महिलाओं के प्रति प्रतिगामी रवैया

महिलाओं के लिए काम करने वाले एक सामाजिक संगठन ने इस दिशानिर्देश पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह महिलाओं के प्रति उसी प्रतिगामी रवैये पर आधारित है जिससे स्पष्ट रूप से लड़ने के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि जब हिंसा का स्रोत कार्यस्थल ही है तो महिलाओं को कार्यस्थल या कार्यबल से क्यों हटाया जाना चाहिए? महिलाओं के लिए काम करने वाले एक अन्य संगठन ने कहा कि दिशानिर्देश अदूरदर्शी, प्रतिगामी और हानिकारक है।

गाइडलाइन महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि महिलाएं राज्य में कहीं भी सुरक्षित और सम्मान के साथ काम कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टरों, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं, गिग श्रमिकों, महिलाओं को रात के दौरान विभिन्न व्यवसायों में काम करना पड़ता है। उनका मानना ??है कि अगर उनके काम के घंटे कम कर दिए जाएंगे तो कई महिलाएं अपनी नौकरी और आय खो देंगी। फिर भी कुछ अन्य लोगों ने कहा कि दिशानिर्देश महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि यदि रात्रि पाली में कटौती केवल महिला डॉक्टरों के लिए है, तो यह दिशानिर्देश एक विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए चयनात्मक सुरक्षा की बू आती है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव : 'महायुति गठबंधन' के क्षेत्र में कठिन होगी 'महाविकास अघाड़ी' की राह, पानी रहेगा प्रमुख चुनावी मुद्दा

मुंबई (एजेंसी)। जलगांव महाराष्ट्र का एक प्रमुख लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से काबिज है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी की स्मिता वाघ ने जीत दर्ज की थी। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से जलगांव क्षेत्र बेहद ही सुंदर माना जाता है। यहां जिला मुख्यालय होने के चलते सभी सरकारी विभागों के बड़े-बड़े दफ्तर भी हैं। बोरी नदी के पास स्थित परोला किला इस क्षेत्र की ऐतिहासिकता की गवाही देता है। इस किले को 1727 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पिता ने बनवाया था। यहां के धार्मिक स्थलों में संत मुक्ताबाई मंदिर एक प्रमुख स्थल है।

जलगांव लोकसभा क्षेत्र जलगांव शहर, जलगांव ग्रामीण, अमलनेर, एरंडोल, चालिसगांव और पचोरा विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है। इन सभी सीटों पर पूरी तरह से %महायुति गठबंधन% का ही कब्जा है। जिसके तहत भाजपा के पास दो सीट, शिवसेना के पास तीन और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास एक सीट है। इस लोक सभा क्षेत्र की जलगांव शहर विधानसभा सीट महाराष्ट्र विधानसभा में 13 नंबर से जानी जाती है। यह विधानसभा क्षेत्र जैन सुरेश कुमार भीकमचंद उर्फ सुरेश जैन के कारण भी पूरे देश में जाना जाता है। उन्होंने इस सीट का 1980 से लेकर 2014 तक लगातार प्रतिनिधित्व किया है। इस दौरान वे कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी समेत दूसरी कई अन्य पार्टियों के टिकट पर भी विधानसभा पहुंचते रहे हैं। 2012 में जलगांव हाउसिंग घोटाले में उन्हें जिला न्यायालय द्वारा दोषी करार दे दिया गया था। इस सीट पर वर्तमान विधायक बीजेपी के सुरेश दामू भोले हैं, जिन पर क्षेत्र के मतदाता लगातार 10 वर्ष से भरोसा जाता रहे हैं।

महाराष्ट्र में 2008 में हुए परिसीमन के बाद 2009 से अस्तित्व में आया जलगांव ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र भी जलगांव जिले के अंतर्गत ही आता है। जहां से एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना के गुलाब रघुनाथ पाटिल 2014 से लगातार विधायक हैं। उनके पहले यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुलाबराव देवकर के पास थी। विधायक रघुनाथ पाटिल 2022 में बनी एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में जल आपूर्ति मंत्री बनाए गए थे। उन्हें पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में भी शामिल होने का अवसर मिला था। देश में हुए पहले आम चुनाव के साथ ही जलगांव लोकसभा क्षेत्र की अमलनेर विधानसभा सीट अस्तित्व में आ गई थी। इस सीट पर 2009 तक भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मजबूत स्थिति में रही थी, लेकिन उसके बाद क्षेत्र के मतदाताओं ने 2009 और 2014 में निर्दलीय उम्मीदवारों पर लगातार दो बार भरोसा जताया। 2019 में अंतिम बार हुए चुनाव में अजित पवार के गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अनिल भाईदास पाटिल चुनाव जीतने में सफल रहे थे। विधायक पाटिल को एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में आपदा नियंत्रण और पुनर्वास मंत्रालय की जिम्मेदारी भी सौंप गई है।

जलगांव लोकसभा क्षेत्र की एरंडोल विधानसभा सीट पूरी तरह से जलगांव जिले के अंतर्गत ही आती है। इस क्षेत्र के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लगभग सभी दलों पर अपना भरोसा जताया है। वर्तमान में शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के चिमनराव पाटिल यहां से विधायक हैं। उनसे पहले एनसीपी के अन्नासाहेब डॉक्टर सतीश भास्करराव पाटिल भी विधानसभा पहुंच चुके हैं। एनसीपी ने 1999 से लेकर 2014 तक लगातार तीन बार इस सीट पर अपना कब्जा जमाकर रखा था। महाराष्ट्र विधानसभा में 17 नंबर से जाना जानेवाला चालिसगांव विधानसभा क्षेत्र पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहा है। 1990 से लेकर 2019 के बीच सिर्फ एक बार ही यह सीट बीजेपी के हाथ से फिसली थी। 2009 के चुनाव में एनसीपी के राजीव दादा देशमुख ने यहां से बीजेपी का लगभग 20 साल का प्रभुत्व खत्म किया था, लेकिन पार्टी ने 2014 में एक

बार फिर यह सीट अपने कब्जे में कर ली। जहां से मंगेश चव्हाण वर्तमान में विधायक हैं।

जलगांव लोकसभा क्षेत्र की पचोरा विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से जलगांव जिले के भीतर ही आता है। यह सीट महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। प्रारंभ में यह सीट लगातार कांग्रेस के पास ही रही थी लेकिन धीरे-धीरे पार्टी ने नियंत्रण खो दिया और उसे पचोरा में अंतिम बार 2090 के चुनाव में जीत हासिल हुई थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अब तक इस सीट पर अपना खाता खोलने में ही असफल रही है। यहां से एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना पिछले 10 साल से चुनाव जीत रही है। जिसके नेता किशोर अप्पा पाटिल वर्तमान में यहां से विधायक हैं।

जलगांव निर्वाचन क्षेत्र जिले का पश्चिमी भाग है। अधिकांश क्षेत्र गिरना नदी बेल्ट के अंतर्गत आता है। इसलिए यहां पानी की कमी है। कुछ तालुकों में हर साल कमी होती है। तीस साल से रुकी पैडलसारे (कम तापमान) परियोजना, गिरना नदी पर गुब्बारा बांध परियोजना, कपास की कीमत में कमी इस क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे होंगे। लगातार बीजेपी के सांसद चुने जाने के बावजूद इन परियोजनाओं का काम पूरा नहीं हो सका है। हालांकि, बलीराजा संजीवनी योजना के तहत पूरा हुआ वरखेड-लोंढे प्रोजेक्ट, फोर-लेन हाईवे और सड़क कार्य सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। चुनाव ऐसे ही मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमेगा।

अस्पताल में पेट दर्द से तड़पता रहा मासूम, मौतः

परिजनों का आरोप-गिड़गिड़ाते रहे, ट्रीटमेंट नहीं मिला;कम्पाउंडर एपीओ

द पुलिस पोस्ट

टोंक। टोंक के सआदत जिला हॉस्पिटल के जनाना अस्पताल में मंगलवार सुबह एक 11 वर्षीय इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए ड्यूटी डॉक्टर समेत इसमें लापरवाह मेडिकल स्टॉफ आदि पर हत्या का केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बच्चे की मां का रो-रो कर बुरा हाल रहा। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से समझाइश की।

रेफर करने के बाद हुई मौत

उधर पीएमओ डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर ने बच्चे को देखा था, हालत खराब होने पर उसे जयपुर रेफर किया था। इसके बाद उसकी कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई।

पेट दर्द होने पर लेकर पहुंचे थे अस्पताल

मृतक के पिता बरोनी थाना क्षेत्र के नला निवासी अशोक बैरवा ने बताया कि उनके बेटे आयुष को मंगलवार अलसुबह करीब 4 बजे पेट दर्द हुआ। उसके बाद उसे निवाई लेकर गए। जहां उसका इलाज किया गया। लेकिन बच्चे की हालात को देखते हुए उसे टोंक रेफर कर दिया।

'जनाना अस्पताल में नहीं मिला डॉक्टर'

परिजन उसे सुबह करीब साढ़े 6 बजे टोंक के जनाना अस्पताल लेकर आए। जहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद परिजन इधर से उधर नर्सिंग स्टॉफ के पास गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनीं। आखिरकार बच्चे ने 2 घंटे बाद करीब साढ़े 8 बजे दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान समाज के कई लोग मौके पर पहुंचे और लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करने की दी रिपोर्ट

उधर सूचना मिलने के बाद टोंक कोतवाल भंवर लाल वैष्णव मौके पर पहुंचे और समझाइश की। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच में आश्वासन पर परिजन करीब साढ़े 10 बजे पोस्टमॉर्टम करवाने पर तैयार हुए। पुलिस ने करीब साढ़े 11 बजे बच्चे के शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने इस मामले में ड्यूटी डॉक्टर समेत अन्य जिम्मेदार मेडिकल स्टाफ के खिलाफ बच्चे की हत्या का मामला दर्ज करने के लिए रिपोर्ट कोतवाल को दी है।

'मरने से पहले बच्चा तड़पने लगा तो वार्ड में लिया था'

मृतक बच्चे के पिता अशोक बैरवा समेत भीम सेना जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा, एडवोकेट विनोद लांबा आदि ने बताया कि बच्चे को समय रहते किसी ने नहीं देखा। निवाई से बच्चे को ड्रिप लगाकर भेजा था। यहां बच्चे को कोई इलाज नहीं दिया गया। बच्चे के ना तो कोई नई ड्रीप चढ़ाई गई और ना कोई अन्य ट्रीटमेंट दिया गया। मरने से थोड़ी देर पहले जब बच्चा तड़पने लगा तो 15-20 वार्ड में लिया था। जहां भी कोई इलाज नहीं किया गया है। चाहे तो अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक कर लो। सब सच सामने आ जाएगा। बच्चे का डॉक्टर तो दूर की बात रही नर्सिंग स्टाफ ने भी इलाज शुरू नहीं किया।

4 भाइयों के परिवार में इकलौता बेटा था आयुष

अशोक बैरवा के 2 बच्चे थे, जिनमे 4 साल की बेटी और 11 साल का आयुष था। अब इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। आयुष कक्षा 6 में पढ़ता था। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक आयुष के पिता 4 भाई है। इन चारों भाइयों के बेटे-बेटियों में आयुष इकलौता बेटा था। इसकी भी मौत से अब इन चारों भाइयों के परिवार में अब बेटा नहीं है।

क्या कहते है पीएमओ

पीएमओ डॉक्टर बीएल मीना ने बताया कि बच्चा यहां रेफर होकर आज सुबह पौने 7 बजे बाद आया था। सुबह 6.52 बजे बच्चे को डॉक्टर ईरफानुद्धीन ने देखा था। 8.03 बजे बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया। लेकिन वे बच्चे को ले नहीं गए। साढ़े 8 बजे बच्चे ने यही दम तोड़ दिया।

मामले में कम्पाउंडर सस्पेंड

जनाना हॉस्पिटल में 2 घंटे तक बच्चे को इलाज नहीं मिलने के कारण बच्चे की हुई मौत के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने अंदर वार्ड में ड्यूटी देने वाले एक नर्सिंग ऑफिसर (कम्पाउंडर) कमलेश बैरवा को सस्पेंड कर उसका मुख्यालय जयपुर कर दिया है।

जांच के बाद नियमानुसार होगी कार्रवाई

कोतवाल भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही से बच्चे की मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। इसकी जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नशा मुक्त सेंटर्स में लापरवाही पर होगी कार्रवाईः

मान्यता रद्द के लिए जिला कलेक्टर राज्य सरकार को लिखेंगे पत्र

द पुलिस पोस्ट

हनुमानगढ़। नशे की रोकथाम कर नशा मुक्त हनुमानगढ़ के लिए संकल्पित जिला कलेक्टर कानाराम गंभीर हैं। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को साप्ताहिक समीक्षा और नशा मुक्त अभियान की बैठक में इसके स्पष्ट संकेत दिए। उन्होंने कहा कि नशे से एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए नशे को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी संवेदनशीलता से आमजन को जागरूक करें। नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए संचालित सेंटर्स की जांच करें। इनमें आवश्यक संसाधनों के अभाव, नियमों की अवहेलना मिलने पर मान्यता रद्द कराने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसे सेंटर्स के लिए वे स्वयं राज्य सरकार को पत्र लिखेंगे। अधिकारियों से कहा कि अभियान को धरातल पर उतारें। नशे से लिप्त स्थानों पर जाकर लोगों से संवाद करें। किराना सहित छोटी-छोटी दुकानों की भी जांच कराएं। पूरे जिले में एक साथ कार्रवाई के बजाय क्षेत्र विशेष में जाकर कार्य करें। कानाराम ने कहा कि जिस तरह हरियालो राजस्थान पौधारोपण में सभी विभागों ने लीड लेकर काम किया। अब उसी तरह कार्य करें। शिक्षा अधिकारी सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स को ई-शपथ दिलाएं। स्कूलों में शनिवार को नशा मुक्त अभियान पर ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराए। राजीविका अपनी मानस सखियों के जरिए घर-घर में जागरूकता कार्यक्रम कराएं। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बड़े ग्रुप्स पर औचक कार्रवाई और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अपने सभी संस्थानों में नशा मुक्त अभियान के टोल फ्री नम्बर और ई-शपथ के क्यूआर कोड चस्पा कराएं। जिला कलेक्टर ने साप्ताहिक बैठक में गोगामेड़ी मेले के दौरान पेयजल और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों और गोशालाओं में पानी कनेक्शन करने, गुणवत्ता जांचने और जल संरक्षण के निर्देश दिए। डिस्कॉम एसई रजीराम सहारण ने बताया कि मेला परिसर में अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर रखवाए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हनुमानगढ़ जिला अग्रणी है। जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर विकास कार्य कराने के निर्देश दिए। कृषि अधिकारी गुलाबी सुण्डी से बचाव, फसलों की देखभाल सहित अन्य विषयों को सोशल मीडिया के जरिए किसानों तक पहुंचाएं। सामुदायिक तारबंदी कराने के लिए किसानों को जागरूक करें। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता चौधरी, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, कृषि संयुक्त निदेशक योगेश कुमार वर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता उपनिदेशक सुरेंद्र पूनिया, सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा सहित विभागीय उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

डीप-फ्रिज में मृत हिरण रख रैली,8 दौर की वार्ता विफलः

गुस्साए लोगों ने NH-62 किया जाम; DFO-रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग

द पुलिस पोस्ट

सूरतगढ़-श्रीगंगानगर। हिरण के शिकार के खिलाफ श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में रविवार को शुरू हुआ आंदोलन तीसरे दिन मंगलवार को भी जारी है। दोपहर 2.15 बजे लोगों ने पठानकोट (पंजाब) से कांडला पोर्ट (गुजरात) जाने वाले नेशनल हाईवे-62 को जाम दिया। शिकार हुए हिरण को डीप-फ्रिज में रख ट्रैक्टर से लोगों ने रैली निकाली। अखिल भारतीय विश्नोई युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित कड़वासरा ने बताया- रविवार को सुबह 6 बजे सूरतगढ़ कस्बे के गांव 64 छठढ निवासी किसान बजरंग पूनिया को झाड़ियों में घायल हिरण मिला था। उसकी गर्दन के पास गोली लगने का निशान था। बजरंग ने वन्य जीव प्रेमियों को सूचना दी। वे हिरण को इलाज के लिए रिड़मलसर वन्य जीव रक्षा चौकी (श्रीगंगानगर) लेकर पहुंचे। लेकिन हिरण ने रास्ते में दम तोड़ दिया था। इसके बाद रायसिंहगर रेंजर जगदेव शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हिरण के पोस्टमॉर्टम के लिए हमने मना कर दिया। रविवार को

हम रिड़मलसर-भगवानगढ़ रोड (सूरतगढ़) पर 9 उष्ठ के रोही क्षेत्र में हिरण के शव को डीप फ्रीज में रखकर धरने पर बैठ गए। रविवार की इस घटना के बाद बिश्नोई समाज और इलाके के लोग आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने नेशनल हाईवे-62 जाम कर दिया। हमारी मांग है कि श्रीगंगानगर डीएफओ दिलीप सिंह राठौड़ और सूरतगढ़ रेंजर वेदप्रकाश को हटाया जाए।

प्रशासन के साथ 8 बार हो चुकी वार्ता

मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे आंदोलन कर रहे लोगों से प्रशासन की 7वें दौर की वार्ता हुई। प्रशासन ने मांगें नहीं मानी तो लोग वार्ता छोड़ चल दिए और नेशनल हाईवे-62 की ओर कूच कर गए। लोगों ने हिरण की बॉडी को डीप फ्रिज में रखकर रैली निकाली। लोग भगवानगढ़ गांव (सूरतगढ़) से लेकर हाईवे स्थित बस स्टैंड तक ट्रैक्टरों, कारों, जीपों और हाईवे की तरफ बढ़ने लगे। यहां भी डीएसपी प्रतीक मील और सदर थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने रैली को रोकने की कोशिश की। लेकिन भीड़ ठल्ल- 62 पर पहुंच ही गई। हाईवे जाम होते ही पुलिस प्रशासन ने कलेक्टर को मामले की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर लोकबंधु एसपी गौरव यादव के साथ दोपहर 3:10 बजे कैंचियां पुलिस चौकी (सूरतगढ़) पहुंचे। जहां आंदोलनकारी वन्य जीव प्रेमियों और ग्रामीणों को वार्ता के लिए बुलाया। कैंचियां पुलिस चौकी पर 40 मिनट तक चली वार्ता भी विफल हो गई।

पुलिस ने यातायात डायवर्ट करवाया

लोगों ने हाईवे के लिए कूच किया तो पुलिस ने सूचना फॉरवर्ड कर श्रीगंगानगर सड़क मार्ग पर गांव गणेशगढ़ और कैंचियां से पहले यातायात को डायवर्ट करवा दिया। वहीं सूरतगढ़ से पहले बीकानेर मार्ग पर राजियासर के पास तिराहे से बड़े और भारी वाहनों को डायवर्ट करवाया गया। चार पहिया सहित अन्य छोटे वाहन जाम स्थल से कई किलोमीटर पहले लिंक सड़क मार्ग से आवागमन करते रहे। अखिल भारतीय बिश्नोई युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित कड़वासरा ने बताया- जिन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उन्हीं को बातचीत करने के लिए भेजा जा रहा है। (बता दें कि श्रीगंगानगर डीएफओ दिलीप सिंह राठौड़ छठे दौर की वार्ता में शामिल थे।) श्रीगंगानगर प्रशासन हमसे बात करे और दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे।

ट्रैक्टर ट्रॉलियों, वाहनों से पहुंचे लोग

रैली और धरने में बड़ी संख्या में लोग हाईवे पर पहुंचे। भारी संख्या में महिलाएं भी हैं। इस दौरान मौके पर सूरतगढ़, सदर थाना, राजियासर थाना और श्रीगंगानगर पुलिस लाइन के 500 जवान तैनात हैं। श्रीगंगानगर एडिशनल एसपी रघुवीर सिंह मौके पर हैं।

विश्नोई समाज की महिला ने शुरू की तपस्या

मंगलवार सुबह 11 बजे 9 उष्ठ के रोही धरना स्थल पर विश्नोई समाज की महिला परमेश्वरी देवी बीच सड़क पर बैठ गई। उन्होंने कहा- मैं तपस्या कर रही हूं। मृत जीव को न्याय नहीं मिला तो यहीं बैठी रहूंगी। जिले में हिरण शिकार की यह यह तीसरी घटना है। हिरण का गोली मारकर शिकार किया गया है, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। जब तक मृत हिरण की आत्मा को न्याय नहीं मिलेगा, यहां से नहीं उठूंगी। 12 अगस्त को बाड़मेर के लीलसर गांव में 10 हिरणों के शव और कुछ अवशेष पड़े हुए थे। होटलों में मांस सप्लाई करने के लिए हिरणों का शिकार किया गया था। घटना से गुस्साए लोगों ने दो दिन तक धरना दिया। मामले में पुलिस ने 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक संपादक उपेन्द्रसिंह राठौड़, अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.डीएल टॉवर, 3ए, विद्याश्रम संस्थानिक क्षेत्र जेएलएन मार्ग जयपुर से मुद्रित एवं भू-तल ऑरबिट मॉल, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित, 99280-96524, पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार, अनिल मलिक (सहसंपादक) 8696750000, पंकज गर्ग (प्रबंध संपादक) 01482-455184, 9214417111